RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./ दुर्ग /94/2020-22

श्रीकंचनपथ

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच
साझा करें अपने मित्रों से
सांध्य दैनिक
दुर्ग-रायपुर-बस्तर संभाग
संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल

वर्ष- 13, अंक - 171 | श्रीकंचनपथ ONLINE | visit us http://www.shreekanchanpath.com | भिलाई, शनिवार 9 अप्रैल 2022 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

मुख्यमंत्री बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की दी बधाई

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और महानवमी की बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम बघेल ने नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवरात्रि देवी उपासना का पर्व है। पूरे देश में नौ दिनों तक देवी के नौ रूपों की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है।

इस अवसर पर घरों, मंदिरों में कन्या भोज कराया जाता है। सीएम बघेल ने कहा कि शक्ति स्वरूपा देवी हमारे घरों में बेटियों के रूप में आती हैं। केवल नौ दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा बेटियों और महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के भाव से हम सच्चे अर्थों में उपासना को सार्थक कर सकते हैं।

शिवरीनारायण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोगों ने देर रात तक उठाया लुत्फ, ममता चंद्राकर के गीतों पर झूमे दर्शक

जांजगीर-चांपा। मानस गायन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता और राम वन गमन पर्यटन परिपथ शिवरीनारायण के पहले चरण के लोकार्पण कार्यक्रम के पहले दिन मेला स्थल में उत्साह का माहौल देखा गया. संध्याकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में पद्मश्री डॉ ममता चंद्राकर के गीतों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। डॉक्टर ममता चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के राजगीत से अपने गीतों के श्रृंखला की शुरूआत की और एक के बाद कई मनमोहक गीत गाकर उपस्थित लोगों को भी गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया. कार्यक्रम में चिन्हारी नाचा पार्टी भी अपने नृत्य और संगीत से लोगों का खूब मन मोहा. कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि राजेश्री महंत डॉ रामसुंदर दास, संस्कृति और पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सहित बड़ी संख्या में दर्शकगण मौजूद थे।

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज पर मुख्यमंत्री भूपेश का तंज- यह तो शकुनि मामा है

'कका' के आगे 'ममा' कहां टिकेगा

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का खैरागढ़ उपचुनाव रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूपेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बदलापुर की राजनीति करने व छत्तीसगढ़ में साढ़े तीन साल में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। इधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने आमसभा में शिवराज सिंह पर पलटवार किया। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि यह तो कंस मामा है... शकुनि मामा है।

सीएम भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि कका के आगे ममा कहां टिकेगा। भूपेश ने प्रदेश सरकार के काम भी गिनाए। उन्होंने कहा कि एमपी के मुख्यमंत्री बताएं हम किसानों को धान की जो कीमत दे रहे हैं, वो दे सकते हैं क्या? हम यहां किसानों का गोबर खरीद रहे हैं, वे खरीद सकते हैं क्या? हम यहां मजदूरों को 7 हजार दे रहे हैं वो दे सकते हैं क्या? किसानों को इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, वह क्यों नहीं देते? भूपेश ने कहा कि पूर्व सीएम डॉ. रमन ने कभी बोनस का पैसा नहीं दिया और न ही 21 सौ रुपये में धान खरीदा।

सीएम भूपेश ने कहा- कका अभी जिंदा है...

सीएम ने कहा कि खैरागढ़ की जनता को जल्द ही नए जिले की सौगात मिलेगी। हम लगातार प्रदेश में जनता की तकलीफों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। 15 साल सरकार चलाने वाले जो नहीं कर पाए हमने तीन साल में वह सब किया है। 17 अप्रैल को खैरागढ़ में कांग्रेस विधायक बनना तय है, क्योंकि कका अभी जिंदा है...। सीएम भूपेश बघेल शनिवार को कानीमेरा में एक बड़ी आमसभा को संबोधित करेंगे। वहीं खैरागढ़ व छुईखदान शहर में रोड शो करेंगे। बता दें कि खैरागढ़ विधानसभा के लिए 12 अप्रैल को मतदान होना है और 16 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। मैदान में कुल 10 प्रत्याशी हैं।

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चार लोगों की मौत, सात घायल, किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे लोग

श्रीकंचनपथ न्यूज

महासमुंद। महासमुंद में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, इसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, सात अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें भी तीन की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, बसना के जमडी गांव के लोग ट्रैक्टर में सवार होकर भालूकोना में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान भालूपतेरा-पझरापाली सड़क पर भालूकोना से पहले ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं। ट्रैक्टर-ट्रॉली में करीब 16 लोग सवार थे।

हादसे के बाद सरायपाली एसडीएम नम्रता जैन भी मौके पर पहुंचीं। इसके बाद उन्होंने बसना के अस्पताल में जाकर घायलों का हाल चाल भी जाना। उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर ने एसडीएम से दुर्घटना की पूरी जानकारी ली और जांच के निर्देश दिए।

हवन पूजन

राम नगर सुपेला दुर्गा मंदिर वार्ड 12 परदेसी चौक अष्टमी पर हवन पूजन

भिलाई। आज चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि और इस तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। अभी मां आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि चल रही है। 02 अप्रैल से शुरू हुआ ये पावन पर्व 11 अप्रैल तक नवरात्रि पारण तक मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का खास महत्व होता है। चैत्र नवरात्रि में पूरे नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना का विधान है। इसके अलावा नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का खास महत्व होता है। वहीं, नवरात्रि में कन्या पूजन करने की भी परंपरा है। कन्याओं को साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। दुर्गाष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन कराते हैं।

सीजेआई बोले: सरकारों में जजों को बदनाम करने का नया चलन शुरू, छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर की टिप्पणी

नई दिल्ली/रायपुर (एजेंसी)। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकारों के द्वारा जजों को बदनाम करने का नया चलन शुरू हो गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफजस्टिस रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) पर विचार करते हुए की। दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश पर एक वकील के सवाल उठाए जाने पर पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए यह बात कही।

हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश को छत्तीसगढ़ सरकार और भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता उचित शर्मा ने शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी। शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि प्राथमिकी रद्द करने का तर्क यह है कि आरोप संभावना पर आधारित है।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, आप जो भी लड़ाई लड़ें, वह ठीक है लेकिन अदालतों को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस अदालत में भी देख रहा हूं। यह एक नया चलन है। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि वे उस बिंदु पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'नहीं, हम हर दिन देख रहे हैं। आप एक वरिष्ठ वकील हैं, आपने इसे हमसे अधिक देखा है। यह एक नया चलन है। सरकारों ने जजों को बदनाम करना शुरू कर दिया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'

सरकार बदलेगी तो राशि भी बदल जाएगी

दवे ने कहा, लोग जिस तरह पैसा जमा करते हैं वह चौंकाने वाला है। तब सीजेआई ने कहा, इस तरह सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। कल जब सरकार बदलेगी और दूसरी सरकार आएगी, तब हजार, लाख हो जाएंगे। द्विवेदी ने अदालत को बताया कि सेवा में शामिल होने के समय प्रतिवादी के पास 11 लाख रुपये की संपत्ति थी। लेकिन अब उसके पास 2.76 करोड़ की सात संपत्तियां है। पीठ मामले में 18 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

अनुमानों और आरोपों पर उत्पीड़न नहीं करने दे सकते

पीठ ने कहा, अनुमानों और आपके आरोपों के आधार पर हम इस तरह के उत्पीड़न को जारी रखने की अनुमति नहीं दे सकते। इस पर दवे ने कहा, यह अनुमान नहीं है। किसी ने 2500 करोड़ रुपये जमा किए हैं। इस पर सीजेआई ने कहा '2500 करोड़ की रकम....। एसएलपी में यह अतिशयोक्ति है।'

यह प्रवृत्ति और प्रतिशोध नहीं : दवे

याचिकाकर्ता के वकील दवे ने कहा, हमने इस मामले में किसी की छवि खराब नहीं की है। कृपया तर्क देखें, यह प्रवृत्ति और प्रतिशोध नहीं है। आरोप आय से अधिक संपत्ति का है। जब प्रतिवादी से पूछताछ की जाएगी और उनसे संपत्ति के बारे में बताने के लिए कहा जाएगा, यदि वह ऐसा करने में सक्षम होंगे तो जांच अपने आप बंद हो जाएगी।

व्यापारी के दुकान व घर पर जीएसटी की रेड, जितना टर्नओवर उतना जीएसटी नही किया जमा, व्यापारियों में मचा हड़कंप

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। भिलाई में स्टेट जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। भिलाई के एक थोक व्यवसायी के यहां जीएसटी की जांच की। टीम के अफसरों ने व्यवसायी के गोडाउन और घर पर छापेमारी की है। अफसरों ने दुकान के संचालक और कर्मचारियों को बाहर जाने से रोक दिया। अफसर जांच के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को पावर हाउस मार्केट स्थित कांतिलाल किराना एंड मर्चेंट में जीएसटी की रेड पड़ी है। टीम ने दुकान संचालक को जांच के लिए सभी बिल वाउचर दिखाने को कहा गया है। टीम के अफसरों ने दूसरे राज्यों से खरीदे जाने वाले एक-एक सामान के बिलों की जांच कर रहे हैं। ऐसा बताया रहा है कि व्यापारी का जितना टर्नओवर है, उतना जीएसटी जमा नहीं किया जा रहा है। गोपनीय शिकायत के बाद जीएसटी टीम जांच के लिए पहुंची है।

इस व्यापारी के यहां दी दबिश

बताया जा रहा है कि सीजी जीएसटी की टीम रायपुर से सुबह 8 से 9 बजे के बीच पावर हाउस सर्कुलर मार्केट स्थित कांतिलाल किराना मर्चेंट दुकान पहुंची। कांतिलाल किराना मर्चेंट ग्रासरी के साथ की सुखे मेवे व मशाला का थोक व चिल्हर विक्रेता बताया जा रहा है। टीम ने पहुंचते ही दुकान के भीतर संचालक से पूरे बिल व वाउचर मांगे और जांच शुरू की। इस दौरान कर्मचारियों को बाहर जाने नहीं दिया गया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जीएसटी टीम को खबर मिली थी कि उक्त व्यापारी द्वारा टर्नओवर के अनुसार जीएसटी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद सीजी जीएसटी की टीम ने कार्रवाई की। फिलहाल यह सामने नहीं आया है कि उक्त व्यापारी के यहां कितने की जीएसटी चोरी का मामला है। फिलहाल टीम द्वारा जांच की जा रही है।

पुलिस की दादागिरी: भिलाई के नेहरू नगर चौक पर ट्रक ड्राइवर से कागजात के नाम पर बदतमीजी

श्रीकंचनपथ न्यूज

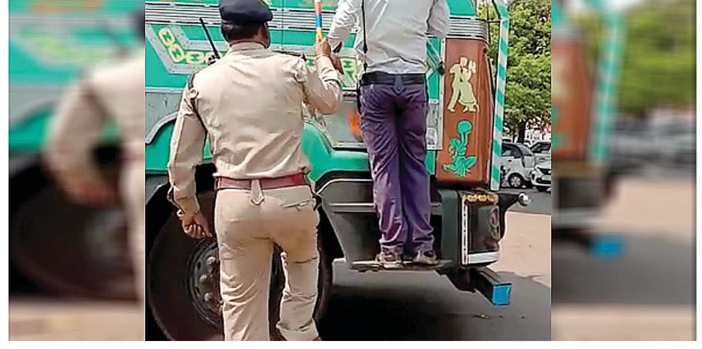

भिलाई। काफी लंबे समय से कुछ पुलिस वालों पर कई सवाल उठते रहे हैं। आज एक बार फिर पुलिस की छवि पर सवाल उठे हैं। मामला भिलाई के नेहरू नगर चौक का है, जहां पुलिस वालों ने दूसरे राज्य के ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर बहसबाजी की और उसे अश्लील गालियां तक दे डाली और डंडे से मारने की कोशिश भी की। ट्रक ड्राइवर का दोष सिर्फ इतना था कि वह सिग्नल पर रुका हुआ था। इसी बीच पुलिस वाले आए और उसे कागजात दिखाने के लिए मांग करने लगे।

ट्रक ड्राइवर जैसे ही नेहरू नगर चौक पर रेड सिग्नल पर रूका पुलिस वालों ने उसके साथ बदतमीजी से पेश आना शुरू कर दिया। उसे गाली गलौज तक करने लगा इतना ही नहीं एक वर्दीधारी तो उसके ट्रक पर चढ़कर उसके ट्रक की चाबी तक निकालने लगा। हालांकि यह पूरा खेल एक कार चालक ने अपने कैमरे पर कैद कर लिया और वीडियो को वायरल कर दिया।

ड्राइवर बार-बार पुलिस वाले से गुहार लगाता रहा कि वह पहली बार कोरोना कॉल के बाद ट्रक लेकर निकला हूं. उसका यह पहला चक्कर है, लेकिन पुलिस वाले ने उसकी एक न सुनी और उसे लगातार पुलिस वाला प्रताड़ित करता रहा। इसके बाद कागजात की जांच हुई कि नहीं इसका पता नहीं चल सका है। लेकिन पुलिस के इस रवैये ने सवाल जरूर खड़े कर दिये हैं।

बूस्टर डोज के लिए नहीं कराना होगा नया रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट के लिए रेट भी तय

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने आज 18-59 आयु वर्ग के लिए बूस्टर डोज यानी एहतियाती खुराक के संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की। इस बैठक में सरकार ने कहा है कि निजी टीकाकरण केंद्र टीकाकरण के लिए सेवा शुल्क के रूप में अधिकतम 150 रुपये तक ही चार्ज कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एहतियात की खुराक उसी टीके की होगी जिसका इस्तेमाल पहली और दूसरी खुराक के लिए किया गया था। साथ ही बूस्टर डोज के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यक्ता नहीं होगा। सरकार का कहना है कि सभी लाभार्थी पहले से ही कोविन पर पंजीकृत हैं।

करंट लगने से ठेकेदार की मौत 25 दिन बाद होनी थी शादी

श्रीकंचनपथन्यूज

धमतरी। छत्तीसगढ़ में एक घर में काम करवा रहे ठेकेदार की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि उसका काम खत्म हो गया था और अपना सामान जमा कर रहा था। इसी दौरान वह छत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों की चपेट में आ गया। उसको करंट इतनी तेज लगा कि वह छत से गिर पड़ा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

सामान समेटने के दौरान हुआ हादसा

मामला कुरूद थाना क्षेत्र का है यहां रभट्ठी निवासी श्याम कार्तिक साहू (26) पेशे से ठेकेदार था। वह मकान निर्माण करवाता था। गुरुवार को भी वह कुरूद के धोबनी तालाब वार्ड में मकान बनाने का काम करवा रहा था। शाम को काम करवाने के बाद उसने जब सामान इक्ट्ठा करना शुरू किया था। उसी दौरान ये हादसा हो गया।

शादी की तैयारियां चल रही थीं

हादसा होने के तुरंत बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि श्याम कार्तिक साहू की सगाई 13 मार्च को हो चुकी थी। 25 दिन बाद 3 मई को उसकी शादी राजिम में होने वाली थी। घर में तैयारियां चल रही थीं।

घर में पसरा मातम

घटना के बाद से ही घर में मातम पसर गया है। शाम होने के कारण गुरुवार को शव का पोस्टमॉर्टम नहीं हो सका था। जिसके बाद शुक्रवार को शव का पोस्टमॉर्टम किया गया है और परिजनों को उसका शव सौंपा दिया है।

संपादकीय

पड़ोस पर नजर

पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने एक बार फिर बेहतर फैसला सुनाते हुए वहां लोकतंत्र को मजबूत करने की बड़ी पहल की है। अदालत ने इमरान खान की सरकार के खिलाफअविश्वास प्रस्ताव पर मतदान को हरी झंडी दे दी है। खास बात यह है कि न केवल इमरान सरकार, बल्कि देश के राष्ट्रपति के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने पलटकर न्याय के प्रति अपने लोगों में विश्वास को बढ़ाया है। अदालत के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बहाल हो गई है, जहां इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। इमरान अपने देश के सफलतम क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वह आखिरी गेंद तक खेलेंगे। अगर वह मतदान से पहले इस्तीफा नहीं देंगे, तो अपने देश में अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर हटाए गए पहले प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इमरान खान ने बहुमत जुटाने के लिए अगर कोई चमत्कार नहीं किया, तो उनका जाना तय है। सभी विशेषज्ञ एकमत हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी संसद में हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास सिर्फ 142 सांसद हैं, जबकि अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने के लिए उन्हें 172 सांसदों की जरूरत है।

> “ इमरान खान या उनके करीबियों पर भी स्याह कमाई के आरोप लगने शुरू हो गए हैं, तो आश्चर्य नहीं। पाकिस्तान में जो भी सरकार अब बने, लोकतंत्र व कानून व्यवस्था का सम्मान करे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नेता परस्पर बेहतर व्यवहार करें। व्यवहारकुशल नेताओं के परस्पर सम्मान से भी जम्हूरियत को बल मिलता है।

संसदीय लोकतंत्र परिपक्वता की मांग करता है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में इमरान सरकार ने खुद को बचाने के लिए संसद को भंग कराया, उससे बहुत त्रासद स्थिति बन गई। जब सरकार को पता था कि वह बहुमत में नहीं है, तब संसद भंग करने की सिफारिश किसी भी लोकतंत्र में निंदनीय कार्य है। गलती करने वालों को कोई दंड या फटकार मिले या न मिले, सबक जरूर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ही नहीं, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर और राष्ट्रपति के लिए भी पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालत का फैसला हमेशा उपयोगी रहेगा। एक सबक यह भी है कि किसी भी सरकार को बाहरी ताकतों की साजिश के बहाने बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के संविधान में यह अतार्किक कमी है, तो उसे दूर करने का प्रयास अगली सरकार को करना चाहिए। अमेरिका या किसी अमेरिकी अधिकारी को दोषी ठहराते हुए खुद को बचाने की इमरान की कोशिश दुखद है। वह इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्हें किन्हीं कारणों से कोई विदेशी ताकत हटाना चाहेगी और यह बात पाकिस्तान के अंदर से भी सामने आई है। अगर ठोस प्रमाण नहीं हैं, तो यही कहा जाएगा कि विदेशी साजिश की बात झूठी है। इमरान को बहाने बनाने के बजाय ठोस प्रमाण सामने रखकर खुद को सही साबित करना चाहिए था। कई बार लगता है, पाकिस्तान के नेता अभी उतने लोकतांत्रिक नहीं हुए हैं, जितना उन्हें अब तक हो जाना चाहिए था। उसका लोकतंत्र नया नहीं है, उसे अभी भी आदर्श या ज्यादा समझदार नेताओं की तलाश है। मजबूत लोकतंत्र ही मजबूत सरकार देने में कामयाब होता है, लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तानी लोकतंत्र को अभी भी चंद नेता अपने हिसाब या मर्जी से हांक रहे हैं। अभी पाकिस्तान में विपक्ष भी प्रशंसनीय नहीं है। भुट्टो परिवार हो या शरीफ परिवार, दोनों के दामन पर बेहिसाब दाग हैं। हालांकि, इन परिवारों की नई पीढ़ी की परख अभी शेष है। इमरान खान या उनके करीबियों पर भी स्याह कमाई के आरोप लगने शुरू हो गए हैं, तो आश्चर्य नहीं। पाकिस्तान में जो भी सरकार अब बने, लोकतंत्र व कानून व्यवस्था का सम्मान करे, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नेता परस्पर बेहतर व्यवहार करें। व्यवहारकुशल नेताओं के परस्पर सम्मान से भी जम्हूरियत को बल मिलता है।

यूक्रेनः भारत ने मुँह खोला

संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारे प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कल यूक्रेन के बारे में जो बयान दिया है, वह विश्व राजनीति में भारत की छवि को तो बेहतर बनाएगा ही, वह रूस को भी अपनी पशुता से बाज आने के लिए शायद प्रेरित कर दे ।तिरुमूर्ति ने यूक्रेन के शहर बूचा में हुए नर-संहार की दो-टूक शब्दों में भर्त्सना की है। उन्होंने मांग की है कि इस नरसंहार की जांच की जानी चाहिए और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। उन्होंने नरसंहार करनेवाले रूस का नाम नहीं लिया। यह सावधानी उन्होंने जरुर बरती लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने रूसी फौज के अत्याचार की उतनी ही सख्त आलोचना की है, जितनी अमेरिका और यूरोपीय देश कर रहे हैं। भारत की इस आलोचना का शायद रूस पर कोई असर न पड़े लेकिन भारत की तटस्थता को अब दुनिया के राष्ट्र भारत का गूंगापन नहीं समझेंगे।

भारत ने हालांकि कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जब भी रूस का विरोध हुआ, भारत ने उसके समर्थन में मतदान नहीं किया लेकिन उसने हर बार यह कहा कि प्रत्येक राष्ट्र को संयुक्तराष्ट्र घोषणा पत्र का सम्मान करना चाहिए, हर देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए और अपने विवादों को युद्ध से नहीं, बातचीत से हल करना चाहिए। तिरुमूर्ति ने यही बात बूचा के नरसंहार पर बोलते ही दोहराई है। मुझे लगता है कि भारत के इस ताजा तेवर से अमेरिका के घाव पर थोड़ा मरहम जरुर लगा होगा, क्योंकि अमेरिका के नेता और अफसर बार-बार भारत से आग्रह कर रहे हैं कि वह रूस-विरोधी तेवर अपनाए और रूस के विरुद्ध घोषित पश्चिमी प्रतिबंधों को भी लागू करे। पश्चिमी राष्ट्रों के ये दोनों आग्रह निरर्थक हैं। वे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और मालदार देश हैं। उनके द्वारा की गई भर्त्सना का क्या असर हो रहा है? इसी तरह का काम अमेरिका ने अफगानिस्तान, लीब्या, एराक, वियतनाम और कोरिया में किया था। यूक्रेनी राष्ट्रपति झेलेंस्की ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा है कि संयुक्तराष्ट्र यूक्रेन की सुरक्षा नहीं कर पाए तो उसको भंग क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए।

-वेद प्रताप वैदिक

> “ धारा नौ में केंद्र को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह इसे लागू करने में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकती है। गृह मंत्री ने भी लोकसभा में इस विधेयक को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार के लिए भेजने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है, यह समिति इन त्रुटियों को दूर करके इस महत्वपूर्ण कानून के माध्यम से अपराध नियंत्रण की पहल को आगे बढ़ाएगी।

ताकि आसानी से पहचाने जाए अपराधी

हरबंश दीक्षित,विधि विशेषज्ञ

बहस की शाश्वत परंपरा और अनुभवों से लगातार खुद को बेहतर करते रहना लोकशाही की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 के संसद से पारित हो जाने के बाद भी इस पर बहस का सिलसिला जारी है। यह कानून 1920 के इसी तरह के कानून की जगह लेगा। इसके माध्यम से केंद्र सरकार अभियुक्तों, अपराधियों व अन्य व्यक्तियों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस बनाना चाहती है, जिसमें गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े लोगों की निजी और बायोलॉजिकल जानकारी होगी। इसे संरक्षित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो को दी गई है। अभिलेख के डिजिटल डाटा को 75 वर्षों तक संरक्षित रखा जा सकेगा, पर यदि कोई अभियुक्त अदालत द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाए, तो उसका डाटा नष्ट कर दिया जाएगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इस सूचना को अपराध नियंत्रण करने वाली अन्य एजेंसियों के साथ साझा कर सकेगा। कानून द्वारा अधिकृत प्राधिकारी हाथ, अंगुलियों और पैरों के निशान, फोटो, रेटीना स्कैन, हस्ताक्षर, फोटो व आवाज के नमूने तथा बायोलॉजिकल सैंपल ले सकेगा। बायोलॉजिकल सैंपल में खून व बाल के नमूने, लार व उनका डीएनए विश्लेषण और उसका सैंपल शामिल है। अधिकृत व्यक्ति को ऐसे नमूने इकट्ठा करने का अधिकार होगा। नमूना देने से इनकार करना दंडनीय जुर्म माना जाएगा।

अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में इस तरह का कानून पहले से ही है और उनके केंद्रीकृत डाटाबेस से अपराध नियंत्रण में बहुत मदद मिली है। अपने यहां महाराष्ट्र में भी यह प्रयोग हुआ है और इससे अपराध पर अंकुश लगाने में उन्हें मदद मिली है। इन्हीं अनुभवों के आधार पर केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अपराध नियंत्रण की दिशा में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। बदलते परिवेश में अपराधियों का व्यवहार तथा उनके तौर-तरीके जटिल होते जा रहे हैं, इसलिए इस तरह का डाटाबेस आवश्यक हो गया है, ताकि अपराध से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें दंडित किया जा सके।

सन 1920 के कानून में मजिस्ट्रेट या सब-इंस्पेक्टर से बड़े रैंक का पुलिस ऑफिसर ही निजी डाटा इकट्ठा करने का निर्देश दे सकता था। मौजूदा विधेयक में इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। अब पुलिस थाने का इंचार्ज, हेड कांस्टेबल और उससे बड़े रैंक के पुलिस अधिकारी तथा जेल के हेडवार्डन को भी ऐसा डाटा इकट्ठा करने के निर्देश देने का अधिकार होगा। कई लोगों को इस पर आपत्ति है, क्योंकि उनका मानना है कि निचली रैंक के अधिकारियों पर चौतरफा दबाव रहता है, उनके लिए निष्पक्षतापूर्ण कार्य करना आसान नहीं होता व अधिकार के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। लोगों का यह भी मानना है कि इस तरह व्यक्तिगत डाटा इकट्ठा करने का निर्णय बहुत संवेदनशील काम है। इसमें लोगों की निजता का अधिकार और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लगती है, इसलिए डाटा या सूचना एकत्रित करने का निर्देश देने का अधिकार मजिस्ट्रेट या जिम्मेदार पुलिस व जेल अधिकारियों को ही होना चाहिए।

नए विधेयक में दोष सिद्ध अपराधियों, अभियुक्तों और निवारक नजरबंदी में निरुद्ध व्यक्तियों को अपनी पहचान से संबंधित डाटा देने के लिए आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा, उन लोगों की पहचान से संबंधित डाटा भी इकट्ठा किया जा सकता है, जो किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तार किए गए हों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं है और तफ्तीश के लिए उसे गिरफ्तार किया गया है, उसका भी सैंपल लिया जा सकता है। मानवाधिकार संगठनों को आशंका है कि 'मैं' शब्दावली इतनी व्यापक है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि सिर्फ शक के आधार पर पकड़े गए लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे और यदि उन्हें बेवजह प्रताड़ित किया जाता है, तो सरकार के खिलाफ बेवजह आक्रोश बढ़ेगा।

अमेरिका, कनाडा व ब्रिटेन में भी इस तरह के कानूनों को लेकर शुरू में वही आशंकाएं थीं, जो आज हमारे यहां जताई जा रही हैं। निजता के अधिकार की भी अपनी एक सीमा है। यह एक व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि अपराध पर नियंत्रण करना सामाजिक जरूरत है। समाज का हित और उसके लिए अपराध पर अंकुश लगाना निजी अधिकारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे देश में अपराधों में दोष सिद्धि की दर अन्य देशों से बहुत कम है। जैसे, अमेरिका में प्रत्येक 100 में से 99.8 अभियुक्त को सजा मिल जाती है, जबकि भारत में बमुश्किल 67 को सजा मिल पाती है। यहां साक्ष्य के अभाव में अधिकतर अपराधी छूट जाते हैं। अपराधियों ने बदलते दौर में अपने तौर-तरीकों में बदलाव किया है। इसलिए उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाना बहुत जरूरी हो गया है। अपराधी संबंधी डाटाबेस बहुत मददगार साबित होगा।

यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पुलिस की कार्य-संस्कृति हमसे इतनी अलग है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कानून लागू करने वाली उनकी संस्थाओं ने पिछले 200 वर्षों में ऐसी कार्य-संस्कृति विकसित की है, जिसमें जान-बूझकर कानून के दुरुपयोग की आशंका धीरे-धीरे नगण्य होती गई है। अपने यहां पेशेवर निष्पक्षता तक पहुंचने में कुछ दशकों का समय लग सकता है। अच्छे कानून या अच्छी व्यवस्थाएं तभी कारगर होंगी, जब हम पुलिस सुधार करेंगे और पुलिस को कानून एवं समाज के प्रति पूरी तरह से जिम्मेदार बनाएंगे। प्रस्तावित कानून की धारा सात में अधिकारियों को सद्भावपूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण दिया गया है, किंतु उन्हें दुर्भावनापूर्ण कार्य के लिए दंडित किए जाने के बारे में यह विधेयक मौन है। ऐसे उपाय होने चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई से आम लोगों को बचाया जा सके। स्वस्थ लोकशाही के लिए यह जरूरी है, ताकि शासन पर जनता का भरोसा कायम रहे।

विधेयक की धारा सात में केंद्र व राज्य सरकारों को इसे लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। धारा नौ में केंद्र को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह इसे लागू करने में आ रही दिक्कतों को दूर कर सकती है। गृह मंत्री ने भी लोकसभा में इस विधेयक को संसद की स्टैंडिंग कमेटी के पास विचार के लिए भेजने का आश्वासन दिया है। उम्मीद है, यह समिति इन त्रुटियों को दूर करके इस महत्वपूर्ण कानून के माध्यम से अपराध नियंत्रण की पहल को आगे बढ़ाएगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

धरती, सेहत और भविष्य के लिए मिलकर पहल की दरकार

पूनम के सिंह,क्षेत्रीय निदेशक, डब्ल्यूएचओ

कोविड-19 महामारी ने उस तंत्रों की विषमता उजागर कर दी है, जिनमें दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के ही नहीं, दुनिया भर के लोग गुजर-बसर करते हैं। विश्व की 90 फीसदी से अधिक आबादी दूषित हवा में सांस लेती है, जिससे हर साल तकरीबन 70 लाख लोगों की जान जाती है। दक्षिण-पूर्व एशिया में भी 24 लाख लोगों की मौत इससे होती है। हमारी खाद्य प्रणालियां भी स्वास्थ्य के लिहाज से असुरक्षित हैं, जिस कारण लाखों लोगों की अकाल मृत्यु होती है। ये खाद्य प्रणालियां जलवायु संकट और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (रोगाणुओं का एंटीबायोटिक्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लेना) बढ़ाने का काम भी करती हैं।

साल 2020 में दुनिया में हर चार में से एक व्यक्ति के घर पर सुरक्षित पानी का अभाव था, और अल्प-विकसित देशों में 50 फीसदी स्वास्थ्य केंद्रों पर ही स्वच्छ पानी की बुनियादी सुविधा थी। गंदा पानी पीने से गंभीर जलजनित रोग हो सकते हैं और आर्सेनिक जैसे जहरीले रसायन हमारे शरीर में पहुंच सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर पानी, साफ-सफाई और स्वच्छता के अभाव के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित होती हैं, जिसका विशेषकर महिलाओं व लड़कियों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि हर साल 1.3 करोड़ से अधिक मौतें उन पर्यावरणीय कारणों से होती हैं, जिनको टाला जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी ने न सिर्फ मौजूदा राजनीतिक, सामाजिक व वाणिज्यिक फैसलों की असमान प्रकृति को बेपरदा कर दिया है, बल्कि इसने यह भी बता दिया है कि यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी, साक्ष्य आधारित और समावेशी हो, तो लोग उन साहसिक और दूरगामी नीतियों का भी समर्थन करेंगे, जो उनकी सेहत, परिवार और आजीविका की रक्षा कर सके। इसने यह भी बताया है कि मौजूदा व आने वाली पीढ़ियों के लिए समान स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर हम कल्याणकारी समाज बना सकते हैं। ये प्राथमिकताएं हम दीर्घावधि के निवेश, कल्याणकारी बजट, सामाजिक सुरक्षा, कानूनी व आर्थिक रणनीतियों से हासिल कर सकते हैं। एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए, जिसमें सभी के लिए स्वच्छ हवा, पानी और भोजन उपलब्ध हो, हमें खासतौर से पांच प्राथमिकताओं पर काम करना चाहिए। यह ऐसा समाज बनाने के लिए भी आवश्यक है, जिसमें आर्थिक नीतियां शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दें, जहां शहर रहने योग्य हों और लोगों की सेहत बेहतर बने।

हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, मानव स्वास्थ्य के स्रोत, यानी प्रकृति की रक्षा व संरक्षण। ऐसी नीतियां चाहिए, जो वनों की कटाई को कम करने, वनीकरण को बढ़ावा देने और गहन व प्रदूषणकारी कृषि कार्यों को खत्म करने में मददगार हों, जो हमारी आबोहवा सुधार सकती हों, खाद्य प्रणालियों को मजबूत बना सकती हों और टिकाऊ कृषि व वन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकती हों। दूसरी प्राथमिकता, स्वास्थ्य केंद्रों पर पानी व स्वच्छता से लेकर स्वच्छ ऊर्जा तक तमाम जरूरी सेवाओं में निवेश करने की है। बहुक्षेत्रीय जल सुरक्षा योजनाओं को लागू करके और स्वास्थ्य संबंधी नीतियों व योजनाओं में पानी, साफ-सफाई व स्वच्छता को शामिल करके तमाम देश स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरी प्राथमिकता, लोगों को तीव्र व स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा की तरफ उन्मुख करना है। वायु प्रदूषण की एक बड़ी वजह जीवाश्म ईंधन हैं। ऐसे ईंधन जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ाते हैं, जिससे साल 2030 और 2050 के बीच सालाना 2.5 लाख अतिरिक्त मौत होने की आशंका है। हमारे क्षेत्र के देशों ने बेशक अक्षय ऊर्जा के विस्तार में सराहनीय प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें और तेजी लाने की दरकार है।

चौथी प्राथमिकता है, स्वस्थ व टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना। भोजन के अभाव या बीमार करने व उच्च कैलोरी वाले आहार से गैर-संचारी रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों से दक्षिण पूर्व एशिया में सालाना 92 लाख लोग मरते हैं। और पांचवीं प्राथमिकता है, स्वस्थ व रहने योग्य शहरों का निर्माण। साल 2021 में दक्षिण पूर्व एशिया के पांच शहरों का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'अर्बन गवर्नेंस फॉर हेल्थ ऐंड वेल-बीइंग इनीशिएटिव' के लिए किया गया था, जिसका मकसद स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और स्वास्थ्यगत विषमताओं को दूर करने के लिए देशों की क्षमताएं बढ़ाना था। साफहै, यह निर्णय की घड़ी है। हमारे फैसले या तो पारिस्थितिक तंत्र को स्थाई नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर एक हरित दुनिया को साकार बना सकते हैं। जाहिर है, अपनी धरती, सेहत और भविष्य की रक्षा के लिए हमें अभी से मिलकर काम करना होगा।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

श्रीमती अंजली जैन की कलम से...

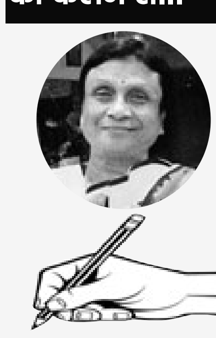

प्रेम अधूरा
संगीत अधूरा
अधूरी है, जीवन
का सफर तुम
बिन।

-अंजली जैन
7024460938

सार्वजनिक शिक्षा स्वास्थ्य का लौटेगा दौर!

अजीत द्विवेदी

बहुत समय नहीं बीता, जब भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सार्वजनिक उपक्रम थे। लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी होती थी। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल सरकारी होते थे। निजी शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों की संख्या बहुत मामूली थी और देश की बहुत छोटी आबादी उनका इस्तेमाल करती थी। आर्थिक उदारीकरण के बाद सुनियोजित तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य की सरकारी व्यवस्था को कमजोर किया गया ताकि निजी शिक्षण संस्थान और अस्पताल फल-फूल सकें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा हुआ। संचार से लेकर परिवहन तक लगभग हर सेक्टर में यह देखने को मिला। सो, सवाल है कि क्या समय का चक्र उलटा घुमाया जा सकता है? क्या सब कुछ पहले की तरह हो सकता है?

हर सेक्टर में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरानी व्यवस्था बहाल हो सकती है। इस उम्मीद के दो कारण हैं। पहला कारण कोरोना वायरस की महामारी है, जिसने सस्ती और बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत को रेखांकित किया है। दूसरा कारण दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा व स्वास्थ्य मॉडल की सफलता है। केजरीवाल ने अपनी तमाम राजनीतिक नाटकीयताओं के बावजूद सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को राजनीतिक विमर्श का केंद्र बना दिया है। गुजरात और दिल्ली मॉडल का यह बुनियादी फर्क है। गुजरात मॉडल के तहत स्कूल-कॉलेज व अस्पताल नहीं दिखाए गए थे, बल्कि औद्योगिक व आर्थिक विकास दिखाया गया था। उसके उलट केजरीवाल दूसरे राज्यों में जाकर अपने स्कूल और अस्पताल दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन दिल्ली आए तो सरकारी स्कूल देखने गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अपने यहां स्कूल विकसित करवाएंगी।

पता नहीं स्टालिन और ममता बनर्जी ऐसा कर पाएंगे या नहीं लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि तीन दशक के बाद समय का पहिया उलटा घूम रहा है। तीन दशक पहले आर्थिक उदारीकरण के साथ यह धारणा बनी थी कि सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है और अगर किसी को अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो उसे निजी स्कूल में भेजना होगा। इसका नतीजा यह हुआ कि गली गली में निजी स्कूल खुलने लगे। सरकारी अस्पतालों के बारे में भी ऐसी ही धारणा बनाई गई। ऐसा नहीं है कि यह धारणा अपने आप बनी।

स्टेशन रोड, इंदिरा मार्केट, दुर्ग के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करे
9827806026, 7869620239

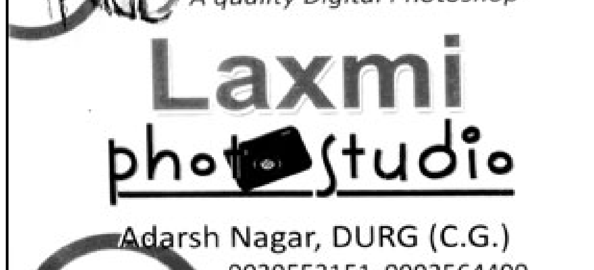

श्रीकंचनपथ
छत्तीसगढ़

इनकम TAX
ITR फाईल
बनवायें मात्र 500/- में
TDS, GST, TAX Expert
सम्पर्क- शेखर गुप्ता
9300755544
onlytds@gmail.com
WWW.ONLYTDS.COM

खास खबर

कलेक्टर ने किया जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण

सुकमा। जिला चिकित्सालय का कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अस्पताल का रंग रोगन सहित साफ-सफाई नियमित रूप से करने के निर्देश दिये। कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मरीज और उनके परिजनों से अस्पताल में सुविधाएं व व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर से चर्चा के दौरान गगनपल्ली जैसे सुदूर अंचल से अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने आये किशके देवा ने बताया कि अस्पताल में हमें कोई असुविधा नहीं हुई है। वहीं अस्पताल में इलाज कराने आई श्रीमती चेतना जैन ने कोई यहां कोई समस्या नहीं आने की बात कलेक्टर से कही। औचक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने आईपीडी सहित विभिन्न कक्षों, अस्पताल में मरीजों के लिए जन सुविधाओं, उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे भोजन, औषधी भण्डारण कक्ष, औषधि वितरण व शेष भण्डारण इत्यादि का सघन मुआयना किया। इस मौके पर अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से चर्चा कर उनका हालचाल जाना तथा चिकित्सों द्वारा स्वास्थ्य लाभ दिए जाने की जानकारी मरीजों से ली। मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। कलेक्टर द्वारा अस्पताल में दवाइयों की उपलब्धता की भी जानकारी ली।कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने हमर लैब, ओपीडी, टीकाकरण, प्रसव की सुविधा एवं ऑपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष, बर्न वार्ड, केजुअल्टी वार्ड, सोनोग्राफी कक्ष, एक्सरे कक्ष, एसएनसीयू कक्ष, लेबोरेटरी कक्ष, ब्लड बैंक आदि का निरीक्षण किया और सुव्यवस्थित सुविधाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन कक्षों का अवलोकन करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।

सदियों से अबूझ रहा माड़ क्षेत्र अब तेजी से बढ़ रहा आगे : मुख्यमंत्री बघेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर को प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर बताते हुए कहा कि यह अंचल वर्षों से पिछड़ा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पिछले साढ़े तीन वर्षों में किए गए कार्यों से इस अंचल में बदलाव नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों से अबूझ रहा यह अंचल भी अब विकास की राह में तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य को देखकर सबसे अधिक खुशी होती है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा लोगों को मसाहती पट्टा देने का परिणाम है कि वे अब खेतों के समतलीकरण और सोलर पंप के साथ ही आधुनिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। शासन की योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिल रहा है। अबूझमाड़ियों के जीवन में आ रहा यह बदलाव उनके जीवन के सबसे अधिक खुशनुमा क्षणों में एक है।

सदियों से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में जिले के विकास हेतु अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने नारायणपुर मैदान परिसर में आउटडोर खेल गतिविधियों हेतु सर्व सुविधायुक्त स्टेडियम निर्माण हेतु 2 करोड़ 57 लाख रूपए, नारायणपुर बंगलापारा में सर्वसुविधायुक्त फुटबाल स्टेडियम हेतु निर्माण 35 लाख रूपए, जिले में 100 घोटुल निर्माण तथा उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी। इसके साथ ही उन्होंने छोटेडोंगर में नवीन शासकीय महाविद्यालय स्थापना की घोषणा करते हुए छोटेडोंगर में 18गढ़ हल्बा समाज भवन के निर्माण हेतु 50 लाख रूपए, कोहकामेटा में सर्व समाज हेतु सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु 50 लाख रूपए, सोनपुर शासकीय माध्यमिक शाला के हाई स्कूल में उन्नयन, ओरछा में पेयजल सुविधा के विस्तार हेतु वॉटर हेड टैंक निर्माण हेतु 50 लाख रूपए, ओरछा विकासखण्ड मुख्यालय में सर्व सुविधायुक्त मिनी स्टेडियम का निर्माण हेतु 45 लाख रूपए की स्वीकृति देते हुए शासकीय जिला अस्पताल नारायणपुर का नाम स्वर्गीय श्री बद्रीनाथ बघेल, पूर्व विधायक नारायणपुर के नाम पर करने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने आज यहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर 251 नव दंपत्तियों को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि नारायणपुर के विकास को गति प्रदान करने के लिए यहां लगभग 128 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि अब तक इन गांवों के 788 किसानों को मसाहती खसरा पुस्तिका देकर उनके जीवन में बदलाव की शुरुआत की जा चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में भी 500 से अधिक किसानों को मसाहती खसरा पुस्तिका प्रदान की जा रही है। अब अबूझमाड़ के हमारे किसान भाई भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ ले रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत अब वे भी अपनी भूमि का समतलीकरण करा सकते हैं। अपने खेतों में डबरी निर्माण कराकर मछली पालन भी कर सकते हैं। सौर सुजला योजना का लाभ उठाकर अपने खेतों के सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का अब वे भी लाभ उठा सकते हैं।

अबूझ रहाश्री बघेल ने कहा कि उद्यानिकी विभाग के माध्यम से भी किसान भाइयों के लिए मिनी बीज किट, टूलकिट नलकूप खनन, ड्रिप सिंचाई, शेड नेट जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नारायणपुर और ओरछा के किसान भाई अब इन योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नदी कछार योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी इन किसान भाइयों मिल रहा है।

शासन ने ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे तेजी के साथ अंदरुनी गांवों तक पहुंचे इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ में नये जिलों और नये अनुभागों और नयी तहसीलों का निर्माण किया जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी तहसीलें थी, जिनके कारण दूर-दराज के गांवों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जैसे छोटे-छोटे कामों के लिए परेशान होना पड़ता था। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में भी परेशानी होती थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए छोटेडोंगर और कोहकामेटा को तहसील बनाने की घोषणा की गई है।

महंत डॉ. राम सुन्दर दास ने शिवरीनारायण में राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

8 से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई है राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। गायन प्रतियोगिता का किया शुभारंभछत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महन्त डॉ राम सुन्दर दास ने आज शिवरीनारायण के मेला ग्राउंड में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महन्त डॉ राम सुन्दर दास ने आज शिवरीनारायण के मेला ग्राउंड में तीन दिवसीय

रामनवमी तथा राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत प्रसिद्ध तीर्थ शिवरीनारायण में पूर्ण हो चुके प्रथम चरण के विकास कार्यों के लोकार्पण के अवसर पर जांजगीर-चांपा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवरीनारायण में रामायण मंडलियों के गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई है।

राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता में 25 जिलों की चयनित मानस मंडलियों के लगभग 350 कलाकार 8-9 और 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रतियोगिता में पहले तीन स्थान पर आने वाली रामायण मंडलियों को पुरस्कृत करेंगे। प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपए विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे।

मूंग, उड़द एवं अरहर की भी होगी समर्थन मूल्य पर खरीदी

हर गोठान में हो गोबर की खरीदी : कृषि उत्पादन आयुक्त

अन्य फसलों की खेती के लिए बढ़ाया गया ऋण लिमिट

रबी वर्ष 2021-22 की समीक्षा और खरीफ2022 का कार्यक्रम निर्धारण

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कहा है कि हर गोठान में गोबर की खरीदी होनी चाहिए। गोधन न्याय योजना, किसानों एवं पशुपालकों की अतिरिक्त आमदनी का यह बढ़िया जरिया साबित हुई है। उन्होंने निर्माणाधीन गोठानों को तेजी से पूर्ण कर वहां भी गोबर खरीदी करने को कहा है। डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि अगले खरीफ वर्ष से राज्य में मूंग, उड़द एवं अरहर की भी समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा खरीदी की जायेगी।

डॉ. सिंह आज बिलासपुर जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में रबी वर्ष 2021-22 की प्रगति की समीक्षा एवं खरीफ वर्ष 2022 के कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में बिलासपुर एवं सरगुजा संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उक्त आशय के निर्देश दिए। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने दिन भर आज यहां कृषि एवं इससे जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का फायदा धान के अलावा अन्य फसलों उत्पादक कृषकों को भी मिलेगा। इसके लिए उन्हें सरकारी खरीदी केन्द्रों पर उपज का बेचा जाना जरूरी नहीं हैं। वह निजी मार्केट में भी अपनी उपज बेचकर न्याय योजना का लाभ उठा सकता है। धान के अलावा अन्य फसलों पर किसान ध्यान दें, इसके लिए सहकारी बैंक से दिये जाने वाले ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है। उन्होंने आगामी सीजन के लिए अभी से किसानों को तैयार कर उनके अनुरूप ऋण वितरण करने के निर्देश दिए हैं।

डॉ. सिंह ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गोठानों को और मजबूत करने को कहा है। गोठान में कृषि विभाग की योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक भी स्थापित किया जा सकता है। गौठान समिति अपने इस्तेमाल के साथ किसानों को रियायती दर पर किराया देकर भी आमदनी अर्जित कर सकती है। उन्होंने विभागीय सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत स्प्रिंकलर, ड्रिप, पम्प आदि अनुदान पर उपलब्ध कराकर किसानों को अन्य लाभकारी फसल उगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उन्होंने रासायनिक खादों के अग्रिम उठाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वितरित उर्वरक की प्रविष्टि तत्काल पॉश मशीन में किया जाना चाहिए। इसमें नियमित रूप से प्रविष्टि नहीं किये जाने पर पूरा स्टॉक दिखाई देता जिससे जरूरत पड़ने पर उर्वरक आवंटन नहीं मिलता है।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि गोठानों में वर्तमान में संग्रहित वर्मी कम्पोस्ट का उठाव इस महीने तक हो जाने चाहिये। उन्होंने कहा कि वर्मी कम्पोस्ट की विक्री में अब दिक्कत नहीं आयेगी। किसानों को प्रति एकड़ एक बोरी के हिसाब से उपलब्ध कराया जायेगा। जैविक खेती की ओर बढ़ने का यह अच्छा प्रयास होगा। उन्होंने वन विभाग द्वारा संचालित गोठान के सक्रिय नहीं होने पर असंतोष जताया। डॉ. सिंह ने बैठक में पशुधन विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, मछली पालन विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने इन गतिविधियों से जुड़े किसानों को केसीसी जारी करने में बैंकों द्वारा लगाई जा रही अड़चनों के निराकरण के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया। कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि मछली पालन आमदनी बढ़ाने और रोजगार का अच्छा माध्यम है। इसमें मार्केटिंग की दिक्कत नहीं होती। गांव में निस्तारी के लिए एक तालाब को छोड़कर सभी तालाबों को मछली पालन के लिए समूहों को आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने उद्यान विभाग की समीक्षा में कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित करते हुए उत्पादों की बिक्री के लिए ब्राडिंग एवं उचित बाजार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।

जिला प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास एवं दृढ़ मनोबल के साथ तैयार हुआ आंगनबाड़ी केन्द्र

श्रीकंचनपथ न्यूज

दंतेवाड़ा। शिक्षा की बुनियाद सिर्फ संसाधनों की उपलब्धता से मजबूत नहीं होती लेकिन बच्चों की शिक्षा की बात हो तो शिक्षण संस्थान में सुविधाओं की मौजूदगी बच्चों में आकर्षण पैदा करती है, जो बाद में उनकी शिक्षा की नींव तैयार करती है। मॉडल आंगनबाड़ी केन्द्रों ने फिर से आंगनबाड़ी केन्द्रों की महत्ता एवं उपयोगिता को बढ़ाया है। आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

इसके लिए नवीन आधुनिक पद्धतियों को अपनाकर बच्चों को सरलतम तरीके से शिक्षा देने की पहल की गई है। आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित हों इसके लिए मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे ही दंतेवाड़ा जिले में मनरेगा योजनान्तर्गत विकासखंड गीदम के ग्राम पंचायतों में मॉडल आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य किया गया है। वे केंद्र जो कि भवन विहीन थे अब वहां भी भवन निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में जिला के भवन

विहीन केंद्रों में 100 मॉडल आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए अलग-अलग गतिविधियां कर बच्चों को सिखाया जा रहा है। जिससे बच्चों में अब रचनात्मक और कलात्मक गतिविधियों के प्रति रुचि बढ़ने लगी है। बच्चों को खेल-खेल में नई चीजें सिखाई जा रही हैं, बच्चों को रोचक ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

भवन की दीवारों पर सुंदर-सुंदर चित्र बनाये गये है। इन कलाकृतियों से नन्हे बच्चों को अक्षर बोध, रंगों की पहचान करना, चित्रों के माध्यम से जानवरों के नाम जानने, प्रारम्भिक स्तर पर अंकों के ज्ञान के साथ-साथ बोलने व समझने में मदद मिलती है। वंही केन्द्रों में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की भी समुचित व्यवस्था की गई है। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोत्तरी हो रही है। वे नियमित प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्र आकर बहुत ही खुश हैं जहां स्वच्छता के साथ पौष्टिक खानपान व स्वास्थ्य की देखभाल भी की जाती है। आंगनबाड़ी में गरम भोजन, खेल की गतिविधि से बच्चे बहुत खुश हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में छोटे बच्चों को शिक्षा तो मिल ही रहा है। इसके साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सुपोषित आहार मिल रहा है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्हें गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुवती माताओं को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

खास खबर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की एजेंसी छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स के इम्पैनलमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए कार्यपालन अभियंता या किसी सरकारी संस्था, केंद्र या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उनसे संबद्ध कार्यालयों में समकक्ष पद से सेवानिवृत्त सिविल अभियंताओं से आवेदन मंगाया गया है। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईटी, एनआईटी या सरकारी अनुसंधान संस्थानों इत्यादि में कार्यरत या सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक ऐसे फैकल्टी मेम्बर जिन्हें सड़क निर्माण या पुल की डिजाइनिंग, पर्यवेक्षण और परामर्शदाता के रूप में काम करने का अनुभव हो, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सड़क निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए शासकीय सेवा वाले ऐसे उम्मीदवार वांछित हैं जिन्हें अपनी सेवानिवृत्ति के पहले के आखिरी दस सालों में से कम से कम पांच साल सड़क निर्माण का अनुभव हो। वहीं पुल निरीक्षण के लिए पुल निर्माण की योजना, डिजाइनिंग या क्रियान्वयन में आठ वर्ष के अनुभव वाले ऐसे उम्मीदवार वांछनीय हैं जिन्हें पुल परियोजना के क्रियान्वयन का कम से कम चार वर्ष का अनुभव हो। कोई उम्मीदवार सड़क और पुल निरीक्षण के लिए उपरोक्त दोनों व्यावसायिक योग्यता एवं मैदानी अनुभव रखता है, तो वह दोनों कार्यों के लिए आवेदन कर सकता है।

स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के लिए सभी व्यावसायिक और शैक्षणिक योग्यता धारण करने के साथ ही आवेदक पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप न लगा हो। कम्प्यूटर और स्मार्ट फोन पर काम कर सकने वाले या निर्धारित समय में इन्हें सीखने के इच्छुक उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को मैदानी अनुभव से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न करने कहा गया है।

स्कूलों में निःशुल्क सायकल, पाठ्यपुस्तक और गणवेश का वितरण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करने के निर्देश

रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न आकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क सायकल, छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तक और गणवेश का वितरण किया जाता है। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समारोह आयोजित कर इन सामग्रियों का वितरण करने के निर्देश लोक शिक्षण संचालन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा संचालित योजनांतर्गत निःशुल्क सायकल का वितरण कक्षा 9वीं की छात्राओं के लिए, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का वितरण कक्षा पहली से दूसरी के छात्र-छात्राओं के लिए और निःशुल्क गणवेश का वितरण कक्षा पहली से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं के लिए किया जाता है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा संभाग, जिला और विकासखण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारियों को जारी आदेश में कहा गया है कि इन सामग्रियों के वितरण के लिए प्रत्येक स्कूल में वितरण कार्य का आयोजित किया जाए। वितरण समारोह में अनिवार्यतः स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत एवं नगरीय निकाय के क्षेत्र में संबंधित निर्वाचित पदाधिकारियों, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति, पालक संघ तथा गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इनकी उपस्थिति में ही इन सामग्रियों का वितरण किया जाए। पूर्व निर्देशानुसार अनिवार्य रूप से सभी सामग्रियों की स्टापपंजी संधारित की जाए। प्रत्येक विद्यार्थियों से पावती ली जाएं और पावती पंजी में उसकी विधिवत प्रविष्टि भी की जाएं।

सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत राज्य में 21 हजार आवास स्वीकृत

बुकिंग की प्राथमिकता के आधार पर हितग्राहियों को आवास आबंटन करने के निर्देश

राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) की राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास मिशन (शहरी) के तहत 126 नगरीय निकायों में 21 हजार 340 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है। उन्होंने योजना के तहत आवासों के आबंटन के लिए प्राथमिकता का आधार निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि जिन हितग्राहियों ने पहले आवास बुक कराए हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास आबंटित किया जाए।

बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के 126 शहरी क्षेत्रों में सबके लिए आवास मिशन (शहरी) योजना के अंतर्गत 21 हजार 340 आवासों का निर्माण, 644 करोड़ 17 लाख 54 हजार रूपए की लागत से कराया जाएगा। योजना में 320 करोड़ 10 लाख केन्द्रांश तथा 176 करोड़ दो लाख चार हजार रूपए राज्यांश की राशि होगी। हितग्राहियों का अंशदान 168 करोड़ पांच लाख 49 हजार रूपए होगा। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रियायती दर पर किराए के मकान, हितग्राही द्वारा स्वयं आवास का निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव सुश्री अलरमेल मंगई डी., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव एनएनएक्का, आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अयाज तम्बोली, संचालक ग्राम एवं नगर निवेश जयप्रकाश मौर्य, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे सहित हुडकों, इंडियन आयल कार्पोरेशन के प्रतिनिधि शामिल हुए।

नशीले पदार्थों के अवैध परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के बरतने के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में नशीले पदार्थों के राज्य में अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोकथाम लगाए जाने के लिए अंतर्राज्यीय स्तर पर समन्वय के साथ ही सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकपोस्ट बनाकर कड़ी निगरानी का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विशेष कार्य बल का गठन किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने कहा है कि नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन से लेकर परिवहन तक कड़ी निगरानी रखी जाए। साथ ही राज्य के सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों की खेती तथा इनके उत्पादन के स्थानों का चिन्हांकन कर उसे नष्ट किया जाए। इसके साथ ही इस कार्य में लगे हुए विशेष कार्य बल के सदस्यों को अवैध नशीले पदार्थों के केन्द्रों की खोजबीन और उसके खिलाफकिए जाने वाले कार्यवाही से संबंधित विशेष प्रशिक्षण भी दिए जाएं। राज्य के सीमावर्ती राज्यों के पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर अवैध नशीले पदार्थों के परिवहन की रोकथाम के संबंध में चर्चा कर समन्वित कार्यवाही की जाए।

बैठक में पुलिस विभाग के (नारकोटिक्स) अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में 33 हजार किलोग्राम गांजे का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। वर्ष 2022 में अब तक साढ़े 16 हजार किलो से ज्यादा अवैध गांजा जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं और परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा, प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ, गृह विभाग के सचिव धनंजय देवांगन, भारत सरकार पुलिस विभाग (नारकोटिक्स) के वरिष्ठ अधिकारी सहित राज्य पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खनिज ब्लॉकों के ऑक्शन के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। भारत सरकार खान मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव संजय लोहिया की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के खनिज ब्लाकों के ऑक्शन के संबंध में केन्द्र एवं छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में खनिज ब्लाकों के ऑक्शन की कार्ययोजना सहित विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के खनिज साधन विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, संचालक जे.पी. मौर्य सहित भारत सरकार के खान मंत्रालय एवं भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण राज्य इकाई के अधिकारी एवं राज्य शासन के खनिज विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

खनिज ऑक्शन के संबंध में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य के चिन्हित 22 खनिज ब्लाकों में 16 खनिज ब्लाकों का ऑक्शन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के 29 खनिजों ब्लाको के ऑक्शन की कार्ययोजना तैयार की जा रही है तथा सात लौह अयस्क के खनिज ब्लाको का ऑक्शन इस माह के अंत तक कर लिया जाएगा। भारत सरकार के खान मंत्रालय के अतिरिक्ति सचिव संजय लोहिया ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ में निर्धारित राजस्व लक्ष्य 7800 करोड़ रूपए के विरूद्ध करीब 12085 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से खनिज ब्लॉकों का ऑक्शन, खनिपट्टा स्वीकृति एवं अन्य अनुषांगिक कार्यों के पूर्ण करने पर अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में भारत सरकार, खान मंत्रालय के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य में एनएमईटी के अंतर्गत अधिक से अधिक खनिज ब्लॉकों का सर्वेक्षण करने के प्रस्ताव खान मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया। बैठक में खनिज ब्लॉकों के ऑक्शन के संबंध में विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर भारत सरकार खान मंत्रालय के प्राधिकारियों से चर्चा एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, जिससे कि आने वाले दिनों में प्रदेश अंतर्गत अधिक से अधिक खनिज अनुदानों का आबंटन किया जा सके। बैठक में संयुक्त सचिव सुश्री पुष्पा साहू एवं अपर संचालक डी. महेश बाबू सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

21 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर ली गई प्राचार्यों की सेवाएं

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राज्य शासन द्वारा स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय में प्राचार्य पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के 21 कर्मचारियों की सेवाएं संबंधित विद्यालय के संचालन एवं प्रबंधन समिति को सौंपी हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम और विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने हाल ही में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्राचार्य और शिक्षकों के पदों की पूर्ति शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश दिए थे।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा आज महानदी भवन नवा रायपुर से जारी आदेशानुसार जिन अधिकारियों-कमचाारियों की सेवाएं संबंधित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सौंपी है। इनमें सर्वश्री सी. एल. साहू प्राचार्य स्वामी आत्मानंद स्कूल रानीतरई जिला दुर्ग को यथावत, राकेश बहादुर सिंग प्राचार्य स्वामी आत्मानंद स्कूल अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव को यथावत, श्रीधर दास प्राचार्य स्वामी आत्मानंद स्कूल दुर्गूकोन्दल जिला कांकेर को यथावत, शिवलाल शर्मा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मसौरा जिला कोण्डागांव से स्वामी आत्मानंद स्कूल कोण्डागांव, जे. शंकर प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल ननसिया जिला रायगढ़ को स्वामी आत्मानंद स्कूल जामगांव-एम जिला दुर्ग, मनेश कुमार सिंग व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डोमा जिला धमतरी को स्वामी आत्मानंद स्कूल कुरूद जिला धमतरी, मायाधर प्रधान व्याख्याता स्वामी आत्मानंद स्कूल पिथौरा जिला महासमुन्द को यथावत, गिरीश चंद्र बेहरा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवभोग जिला गरियाबंद को स्वामी आत्मानंद स्कूल देवभोग जिला गरियाबंद, केशव प्रसाद देवांगन व्याख्याता एलबी स्वामी आत्मानंद स्कूल भाटापारा जिला बलौदाबाजार को यथावत, आशीष कुमार शर्मा व्याख्याता एलबी स्वामी आत्मानंद स्कूल सिमगा जिला बलौदाबाजार को यथावत रखा गया है।

इसी प्रकार सुश्री सुजाता बेहल व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कामता विकासखण्ड सिमगा जिला बलौदाबाजार को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कुंरा जिला रायपुर, प्रीशी एक्का व्याख्याता स्वामी आत्मानंद स्कूल कुआकोण्डा जिला दंतेवाड़ा को यथावत, मनोज कुमार सोनकल्हारी व्याख्यता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धौराभाटा जिला राजनांदगांव को स्वामी आत्मानंद स्कूल डोंगरगांव जिला राजनांदगांव, वाय श्रीनिवास राव व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जादुटोला जिला राजनांदगांव को स्वामी आत्मानंद स्कूल डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव, डोन सिंग वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सम्बलपुर जिला बेमेतरा से स्वामी आत्मानंद स्कूल अभनपुर जिला रायपुर, नीलम कौर प्रभारी प्राचार्य स्वामी आत्मानंद स्कूल अर्जुन्दा जिला बालोद को यथावत, त्रिलोक सिंह व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरेली जिला कोरबा से स्वामी आत्मानंद स्कूल करतला जिला कोरबा, गीता सिंह व्याख्याता स्वामी आत्मानंद स्कूल अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा को यथावत, अनिल कुमार शर्मा व्याख्याता शासकीय हाई स्कूल डोंगरी जिला जांजगीर-चांपा को स्वामी आत्मानंद स्कूल बलौदा जिला जांजगीर-चांपा, हेमचरण पटेल व्याख्याता एबी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुर जिला सरगुजा को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय डभरा जिला जांजगीर-चांपा और रामाश्रय शर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया की सेवाएं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया को प्राचार्य पद पर पदस्थ करने के लिए सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ में जल्द ही शुरू होगा ग्रामीण उद्योग केंद्रों की स्थापना का कार्य

ग्रामीण औद्योगिक केन्द्रों की रूपरेखा निर्धारण हेतु कार्यशाला संपन्न

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। गांवों में रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने और किसानों, युवाओं, महिलाओं को उन्हीं के गांवों में नवाचार और उद्यम से जोड़ने की फ्लैगशिप योजना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के अंतर्गत ग्रामीण उद्योग केंद्रों की स्थापना के लिए रूपरेखा तैयार करने कार्यशाला का आयोजन राज्य योजना आयोग द्वारा योजना भवन नवा रायपुर में किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यशाला में ग्रामीण उद्योग केंद्रों के कार्यक्षेत्र क्रियान्वयन के सबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस मौके पर विभिन्न विभाग के उपस्थित अधिकारियों ने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के क्रियान्वयन एवं संचालन पर अपने सुझाव दिए, इसके आधार पर योजना के आगामी क्रियान्वयन के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने पर भी गहन विमर्श हुआ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में के केन्द्र में किसान न्याय योजना और नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना का महत्वपूर्ण उल्लेख है। जिसका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनियोजित ढंग से हो रहा है। इसकी चर्चाएं राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। हमारी योजना को अन्य राज्यों ने अपने यहां लागू करने, विचार करने के उद्देश्य से टीमें छत्तीसगढ़ आ रही हैं। गांधी ने जिस ग्राम स्वराज की संकल्पना की थी, छत्तीसगढ़ सरकार उसे साकार कर रही है। सिंह ने कहा कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम गौठानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर संग्रहण, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था की जा सके। युवा किसानों को उद्यम नवाचार से जोड़ने, गांव के पढ़े-लिखे युवा जो गांव में ही रहकर कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, उन्हें दिशा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा ने बताया कि हम गौठानों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रीढ़ के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, प्रथम चरण में गौठानों में गाय के संधारण, गाय से संबंधित इंडस्ट्रीज के लिए कार्य हुआ। अब हम दूसरे चरण में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का विकास करेंगे। 85 हजार महिलाओं ने मिलकर 56 लाख क्विंटल गोबर खाद का उत्पादन किया है, वर्तमान में देश में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा 20 लाख क्विंटल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हमारे पास तैयार सुरक्षित है। महिला समूहों को अब तक 36 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है।

नंदनी रोड, लिंक रोड, सर्कुलर मार्केट, जवाहर मार्केट पावर हाउस, भिलाई के प्रतिष्ठित संस्थान विज्ञापन के लिए संपर्क करें:-
9303289950, 9827806026, 8962815243

ऐसी आदतें बन सकती हैं गठिया की समस्या का कारण, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

आर्थराइटिस या गठिया, जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बनने वाली एक सामान्य समस्या है। इंफ्लामेंशन की प्रतिक्रिया में शरीर द्वारा उत्पन्न रसायन अक्सर सूजन का कारण बनते हैं। गठिया से पीड़ित लोगों को सामान्य गतिविधियों को करने में भी दर्द का अनुभव होता रह सकता है। सामान्य तौर पर जीवनशैली की गड़बड़ आदतों को गठिया का प्रमुख कारण माना जाता है, इसके अलावा कुछ लोगों में इसका आनुवांशिक जोखिम भी हो सकता है। गठिया की समस्या आपके सामान्य कामकाज को प्रभावित कर देती है, ऐसे में सभी लोगों को इससे बचाव के निरंतर उपाय करते रहने चाहिए।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो समय के साथ लोगों में बढ़ती शारीरिक निष्क्रियता और आहार में पौष्टिकता की कमी के कारण गठिया के मामले पहले की तुलना में काफी बढ़ गए हैं। इसके अलावा जंक और प्रोसेस्ड खान-पान का भी इसमें मुख्य रोल माना जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक समय तक इसे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली समस्या के तौर पर देखा जाता था, वहीं अब 40 से कम आयु वाले लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे गड़बड़ आदतें आर्थराइटिस का कारण बन सकती हैं, जिनको लेकर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है?

शरीर का वजन बढ़ना

आपका बढ़ा हुआ वजन सिर्फ हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियां ही नहीं, आर्थराइटिस की समस्या का भी कारण हो सकता है। हाल के शोध से पता चलता है कि 30 या उससे अधिक के बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले लोगों में रूमेटाइड आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। वजन अधिक होने से, विशेषकर पैर के घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है जिसके कारण गठिया की समस्या का जोखिम बढ़ जाता है। वजन को नियंत्रित रखना कई मायनों में आपके लिए आवश्यक है।

धूम्रपान के कारण गठिया की जटिलताएं

धूम्रपान को सबसे हानिकारक आदतों में से एक माना जाता है, इसके कारण गठिया की समस्या बढ़ सकती है। एक स्वीडिश अध्ययन से पता चलता है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के एक तिहाई मामलों के लिए धूम्रपान को प्रमुख कारक माना जा सकता है। इसके अलावा, धूम्रपान, गठिया की कुछ दवाओं की प्रभावशीलता को भी कम कर सकता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ों के दर्द में वृद्धि का भी कारण बनता है। सभी लोगों को इस आदत से बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए।

ऊंची एड़ी वाली सैंडिल या खराब जूते पहनना

ऊंची एड़ी वाली सैंडिल को फैशन का सूचक माना जाता है, हालांकि यह आपके लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। ऐसे सैंडिल पैरों को एक अजीब स्थिति में रखती हैं जो जोड़ों पर जोर पड़ने का कारण बन सकती है। इसके अलावा अगर आपके जूते की गुणवत्ता ठीक नहीं है तो इससे भी गठिया की समस्याओं के बढ़ने का जोखिम हो सकता है।

डॉक्टर्स बताते हैं कि जो महिलाएं रोजाना हील्स पहनती हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस और पैरों में दर्द होने का खतरा अन्य की तुलना में अधिक होता है। हमेशा पैरों को आराम देने वाले जूते-चप्पल ही पहनें।

स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है विटामिन-ई का सेवन, इन गंभीर समस्याओं से मिलेगी सुरक्षा

शरीर के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उचित पोषण बेहद आवश्यक है। इसके लिए स्वस्थ आहार की विशेष भूमिका होती है। स्वस्थ आहार में तमाम प्रकार के विटामिन्स, खनिज, और प्रोटीन से भरपूर चीजों को शामिल करने पर जोर दिया जाता है। सामान्यतौर पर हम विटामिन-सी और डी की आवश्यकताओं के बारे में खूब सुनते आ रहे हैं, पर सिर्फ यही पर्याप्त नहीं हैं। शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए कई और प्रकार के पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, विटामिन-ई भी उनमें से एक है। इसका नियमित सेवन करना आवश्यक माना जाता है।

विटामिन-ई, शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव वाला होता है, जो शरीर को कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित रखने में विशेष भूमिका निभाता है। विटामिन-ई कुछ खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है, जिसमें सीड्स, नट्स, कुछ फल-सब्जियां हो सकती हैं। इनका दैनिक रूप से सेवन किया जाना आवश्यक माना जाता है। विटामिन-ई की कमी से मुख्य रूप से त्वचा और बालों की समस्या होने का खतरा रहता है। आइए जानते हैं कि विटामिन-ई का सेवन सुनिश्चित करना किन मामलों में फायदेमंद है और इसकी पूर्ति कैसे करें।

एंटीऑक्सीडेंट गुणों से युक्त

शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों (आरओएस) के संचय में असंतुलन के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की समस्या होती है। इससे सेलुलर डैमेज का खतरा बढ़ जाता है, जो कई तरह की गंभीर बीमारियों का कारण हो सकती हैं। चूंकि विटामिन-ई शरीर में एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, ऐसे में अध्ययनों से पता चलता है कि इसका सेवन सुनिश्चित करके इन समस्याओं से बचाव किया जा सकता है।

हृदय रोगों से बचाव

विटामिन-ई का पर्याप्त मात्रा में सेवन उच्च रक्तचाप और बैड कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को नियंत्रित बनाए रखने में सहायक है। यह आपमें हृदय रोग विकसित होने के खतरे को कम करने वाला विटामिन है। शोध से पता चलता है कि विटामिन-ई की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले लोगों में हृदय रोगों का जोखिम कम होता है। 18 अध्ययनों की समीक्षा में पाया गया कि विटामिन-ई की खुराक रक्तचाप को नियंत्रित रखने में सहायक है।

त्वचा और बालों को मिलता है लाभ

विटामिन-ई का सेवन त्वचा और बालों को सेहतमंद बनाए रखने में काफी मददगार माना जाता है। एक्जिमा जैसे त्वचा विकार वाले लोगों को विटामिन-ई सप्लीमेंट से लाभ मिल सकता है। यह बालों के विकास और मजबूती को बनाए रखने वाला पोषक तत्व है। आहार के माध्यम से इसका नियमित सेवन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह आपकी त्वचा को कई प्रकार से लाभ दे सकता है।

विटमिन ई के स्रोत

सामान्य दैनिक आहार से विटामिन-ई के दैनिक आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति की जा सकती है। सूरजमुखी और सोयाबीन का तेल, बादाम और मूंगफली, पीनट बटर, चुकंदर, पालक और कद्दू के साथ लाल शिमला मिर्च में इस पोषक तत्व की प्रचुरता होती है।

हैट्रिक से आगे निकल चुके अजय देवगन की नई उड़ान, बोले, मैं मैथड एक्टिंग में विश्वास नहीं करता

हिंदी सिनेमा का इतिहास इन दिनों कोरोना संक्रमण काल के पहले और कोरोना संक्रमण काल की कामयाबियों पर लिखा जा रहा है। जनवरी 2020 में रिलीज हुई अजय देवगन की ओम राउत निर्देशित फिल्म 'तानाजी द अनसंग वॉरियर' की शानदार कामयाबी के बाद अब जाकर हिंदी सिनेमा या कहें हिंदी में डब सिनेमा ने कामयाबी की रफ्तार पकड़ी है। अजय ने कोरोना महामारी के पहले आखिरी हिंदी हिट फिल्म दी और कोरोना महामारी के बाद की लगातार तीन कामयाब फिल्मों 'सूर्यवंशी', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'आरआरआर' में भी अजय देवगन ने शानदार पारी खेली। अब बारी 'रनवे 34' की है। लगातार चार फिल्मों की कामयाबी के बाद अजय देवगन अब कामयाबी का पंच महायज्ञ करने उतर रहे हैं। ये फिल्म 29 अप्रैल को रिलीज होगी।

अपनी लगातार हिट फिल्मों की चर्चा चलने पर अजय देवगन कहते हैं, ईमानदारी की बात तो यह है कि खड़े हो कर घूरते रहने का समय ही नहीं है। चाहे वह 'सिंघम' हो, 'रहीम लाला', 'वेंकट राम राजू' हो या कैप्टन विक्रांत खन्ना हो, इनमें से हर रोल चुनौतीपूर्ण है। मैं पीछे

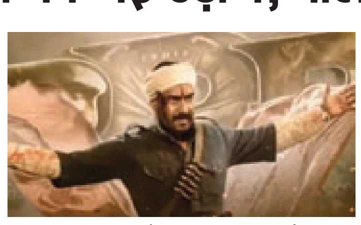

मुड़कर देखने और जायजा लेने के लिए कभी रुका ही नहीं। इसके बजाय मैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक के बाद दूसरी फिल्म करता चला गया। यहां मौजूद मेरे ज्यादातर साथी उतने ही जोशीले और मेहनती हैं। मुझे पता है कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो कुछ खास हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं वैसा ही हूं, जैसी फिल्में बनाता हूं।'

अजय देवगन को कभी कामयाबी पर इतराते नहीं देखा गया। फिल्म दर फिल्म वह हिंदी सिनेमा से मिले उपनाम 'मिस्टर भरोसेमंद' को और चमकाते जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में अक्षय कुमार और रणवीर सिंह के साथ रोहित शेट्टी के पुलिस यूनीवर्स वाली फिल्म 'सूर्यवंशी' में अपनी सीटीमार एंट्री के दम पर अजय ने जोरदार तालियां बजवाईं। फिर इसी साल फरवरी में उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' में डॉन रहीम लाला के किरदार में रोमांचक एंट्री मारी। और एस एस राजामौली की फिल्म 'आरआरआर' में उनका किरदार कहानी के उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) के रूप में नजर आ रहा है।

फिल्म जगत में तीन दशक गुजारने के बाद भी अजय अपनी रफ्तार धीमी करने के कोई संकेत नहीं दिखा रहे हैं। 29 अप्रैल को रिलीज होने जा रही एविएशन थ्रिलर 'रनवे 34' उनकी अदाकारी के साथ साथ निर्देशन का भी एक और टेस्ट है। इस फिल्म में वह फ्लाइट कमांडर कैप्टन विक्रांत खन्ना की भूमिका निभा रहे हैं।

'आरआरआर' और 'द कश्मीर फाइल्स' की सक्सेस पर शाहिद कपूर बोले- यह देखकर अच्छा लगता है कि लोग सिनेमाघर जा रहे हैं

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म 'जर्सी' जल्द बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। यह फिल्म पिछले साल दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की वजह से इसकी रिलीज को रोक दिया गया था। अब हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान शाहिद ने फिल्म से जुड़ी कई बातें शेयर कीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यह देखकर अच्छा लग रहा है कि लोग फिर से सिनेमाघर जा रहे हैं।

शाहिद को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना इतनी तेजी से बड़ जाएगा

शाहिद ने कहा, अमन (निर्माता) और मैं, ओमिक्रॉन (कोरोना वैरिएंट) पर बहुत बारीकी से नजर रखे थे। हमें पता था कि यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में चीजें बदल जाएंगी। बड़ते केस को देखते हुए हमने फिल्म की रिलीज को टालने का फैसला किया। हम नहीं चाहते थे कि यह फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज हो जब सब कुछ ठीक नहीं है। अब मुझे लगता है कि हमने फिल्म को आगे बढ़ाने का सही फैसला लिया था।

शाहिद 'जर्सी' को थिएटर में ही रिलीज करना चाहता थे

शाहिद ने आगे कहा, यह देखकर अच्छा लगता है कि लोग फिर से सिनेमाघर जा रहे हैं। मुझे 'जर्सी' को ओटीटी पर रिलीज करने के लिए कई ऑफर मिले थे, लेकिन हम इसे थिएटर में ही रिलीज करना चाहते थे। बता दें हाल ही में कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई हैं और सबने अच्छी कमाई की है। इनमें 'गंगूबाई', 'द कश्मीर फाइल्स' और 'आरआरआर' शामिल हैं।

मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी हैं फिल्म में अहम भूमिका में

गौतम तिन्नुरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में शाहिद के साथ-साथ मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी अहम भूमिका में हैं। फिल्म में मृणाल उनकी पत्नी की भूमिका में हैं। साथ ही शाहिद के पिता पंकज कपूर फिल्म में कोच की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में दिखाया है कि कैसे एक खिलाड़ी क्रिकेट छोड़ देता है और बेटे की जर्सी खरीदने के लिए दोबारा मैदान में उतरता है। इस फिल्म को 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा।

एक्टर विल स्मिथ पर बैन

अब ऑस्कर में 10 साल तक पार्टिसिपेट नहीं कर सकते

ऑस्कर सेरेमनी के दौरान हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ को कॉमेडियन क्रिस रॉक पर थप्पड़ मारना भारी पड़ गया है। एकेडमी मोशन ऑफ पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (ऑस्कर) ने विल स्मिथ पर शुक्रवार को बैन लगा दिया। इस फैसले के बाद विल अगले 10 साल तक ऑस्कर के किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे।

एकेडमी के अध्यक्ष डेविड रुबिन ने कहा कि, इस साल के ऑस्कर सेरेमनी के दौरान मंच पर क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने की वजह से यह फैसला लिया गया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति जताई है। डेविड ने कहा कि घटना के बाद विल को हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में बैठने की अनुमति दी गई और उन्हें पुरस्कार भी दिया गया, जिसके बाद एकेडमी की आलोचना होने लगी थी।

27 मार्च को लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वी ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी आयोजित हुई थी। इसी दौरान मंच पर कॉमेडियन क्रिस रॉक ने एक्टर विल स्मिथ की पत्नी जेडा पिंकेट की बीमारी को लेकर एक मजाक किया। मजाक से विल नाखुश हो गए और अपनी सीट से उठकर मंच पर जाकर क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही विल ने क्रिस को वॉर्निंग देते हुए कहा कि मेरी पत्नी का नाम कभी भी अपनी जुबान पर मत लाना।

दरअसल, क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी एक्ट्रेस-सिंगर जेडा पिंकेट के गंजेपन को लेकर मजाक किया था। पिंकेट ने बीमारी की वजह से अपने बाल कटवाए थे। दरअसल, वो एलोपीशिया बीमारी से जूझ रही हैं, जिसकी वजह से सिर में जगह-जगह से बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं।

विल दे चुके है मोशन पिक्चर ऑफ एकेडमी से इस्तीफा

कॉमेडियन को थप्पड़ मारने के बाद विल ने 29 मार्च को मोशन पिक्चर ऑफएकेडमी से इस्तीफा दे दिया था। विल ने इस्तीफे के बाद अपने बयान में कहा था कि मैंने जो हरकत की है वो बेहद शर्मनाक और हैरान कर देने वाली थी। जिन लोगों को भी मैंने दर्द दिया है, मैं उन सबसे माफी मांगता हूं। मैंने अकेडमी के विश्वास के साथ धोखा किया है। बोर्ड जो भी फैसला लेगा वह मेरे लिए स्वीकार होगा।

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड-बेमेतरा (छ.ग.)

Gov.mail: eeprobem.phe-cg@nic.in

ई-प्राक्योरमेंट द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना

ऑनलाईन निविदाएं प्रपत्र-ए में प्रतिशत दर पर अनुबंध हेतु नीचे उल्लेखित कार्यों के लिये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में एकीकृत पंजीयन व्यवस्था में श्रेणी-डी एवं उच्च में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

नि.आ.सू.क्र. एवं दिनांक	सिस्टम क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू. लाख में)
01/06.04.2022	96816	राजीव गांधी सर्व जल योजना अंतर्गत ग्राम सिंघौरी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑफिस बिल्डिंग का कार्य	45.69

टीप:- उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत विवरण, निवदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल http://epro.cgstate.gov.in में दिनांक 13.04.2022 से देखी जा सकती है एवं निविदा की **अंतिम तिथि 25.04.2022** है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी परियोजना खण्ड
बेमेतरा (छ.ग.)

जी-90145/4

खास खबर

ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या न हो - कलेक्टर

बालोद। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने कहा कि जिले में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या न हो। किसी भी प्रकार की समस्या पर उसका तत्काल निदान किया जाए। जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम नियमित संचालित रहे। महोबे आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन तथा नगरीय निकायों के अधिकारियों को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी ग्रामों एवं नगरीय निकायों में हैण्डपम्प एवं बोर चालु हालत में रहे। ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में पेयजल समस्या की शिकायतों एवं निराकरण संबंधी पंजी संधारित किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में लू और जल जनित संक्रामक रोगों से बचाव एवं रोकथाम के लिए मुनादी कराएँ तथा जनजागरूकता लाएँ। उन्होंने सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में लू और जल जनित रोगों से बचाव हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाईयाँ तथा ओ.आर.एस. पैकेट का भण्डारण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में जल की उपलब्धता की जानकारी ली और आवश्यक दिशानिर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि पेयजल की समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर तथा विकासखण्ड स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना कर ली गई है।

छत्तीसगढ़ के शिवरीनारायण में अब जीवंत होगी किवदंतियां

रायपुर। छत्तीसगढ़ से जुड़ी भगवान राम के वनवास काल की स्मृतियों को सहेजने तथा संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना शुरू की गई है। चंदखुरी के बाद अब शिवरीनारायण में भी विकास कार्य पूरा हो चुका है, जिसका लोकार्पण 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके लिए तीन दिवसीय भव्य राष्ट्रीय समारोह का शुभारंभ आज शिवरीनारायण में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ। जांजगीर-चांपा जिले में प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण शिवनाथ, जोंक और महानदी का त्रिवेणी संगम स्थल शिवरीनारायण है। इस विष्णुकांक्षी तीर्थ का संबंध शबरी और नारायण होने के कारण इसे शबरी नारायण या शिवरीनारायण कहा जाता है। ये मान्यता है कि इसी स्थान पर माता शबरी ने वात्सल्य वश बेर चखकर मीठे बेर रामचंद्र जी को खिलाए थे। यहां नर-नारायण और माता शबरी का मंदिर है जिसके पास एक ऐसा वट वृक्ष है, जिसके पत्ते दोने के आकार के हैं। पर्यटन तीर्थों की नयी श्रृंखला आकार लेने लगी है।

पीएमएमवाई के ऋण खातो की संख्या 34.42 करोड़ हुई

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली (पीआईबी)। वित्तीय समावेश के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की शुरुआत की गयी थी। हम इस योजना की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए हम इस योजना की कुछ प्रमुख बातों और उपलब्धियों पर एक नज़र डालें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को पीएमएमवाई का शुभारम्भ किया था, जिसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट व गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करना था।

योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, उल्लेखनीय है कि आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए इस योजना के तहत कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के लिए 34.42 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं।

पीएमएमवाई के माध्यम से कारोबारी माहौल में सुधार और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के बारे में वित्त मंत्री ने कहा, योजना ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद की है और जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किये हैं। 68 प्रतिशत अधिक ऋण खाते, महिलाओं के लिए स्वीकृत किये गए हैं और 22 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को दिये गए हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से अब-तक ऋण नहीं लिए हैं।।

सभी मुद्रा लाभार्थियों को बधाई देते हुए और अन्य संभावित उधार लेने वालों से आगे आने तथा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, अब तक स्वीकृत कुल ऋणों में से 51 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति / ओबीसी श्रेणी समुदाय को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है तथा इस अर्थ में %सबका साथ, सबका विकास% भावना की सच्ची प्रतीक है, जो माननीय प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप है।

इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने कहा की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) शुरू करने के पीछे की प्रेरक शक्ति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परेशानी मुक्त / निर्बाध तरीके से संस्थागत ऋण प्रदान करना है। अपनी शुरूआत के बाद से, पिछले सात वर्षों में, कुल 34.42 करोड़ खाताधारकों को सहायता प्रदान करते हुए यह योजना उत्साही उद्यमियों को सफलतापूर्वक लाभ पहुंचा रही है, वित्त राज्यमंत्री ने कहा ।

वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड ने कहा की इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने वाले कई उद्यमी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस योजना के तहत सबसे बड़ा लाभार्थी समूह महिलाओं का है। इस योजना के तहत खोले गए ऋण खातों में से 68 प्रतिशत से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इस योजना के अंतर्गत चलाए गए विशेष अभियान ने भी महिलाओं और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए संभावित ऋणकर्ताओं तक पहुंचने में मदद की है। पीएमएमवाई का अन्य उल्लेखनीय फोकस नीति आयोग द्वारा चिन्हित किए गए 'आकांक्षी जिलों' में अधिक से अधिक संख्या में लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना है और इस प्रकार ऋण से वंचित इन जिलों में ऋण के प्रवाह को अनुकूल बनाना है, वित्त राज्यमंत्री डॉ. कराड ने कहा।

देश में वित्तीय समावेश (एफआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन स्तंभों पर आधारित है, अर्थात, बैंक की सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सुविधा देना, असुरक्षित ऋण को सुरक्षित बनाना और वित्तीय सुविधा से वंचित लोगों को वित्तीय सुविधा देना। इस कार्यक्रम के तहत, प्रौद्योगिकी की मदद से और विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इन तीन उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं और इसके साथ ही जरूरी सुविधाओं से वंचित लोगों को सहायता भी प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिलेवासियों को 127.83 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी

सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 251 जोड़े बंधे दाम्पत्य जीवन में: मुख्यमंत्री ने उन्हें खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए दिया आशीर्वाद

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। विकास कार्यों की सौगात दीमुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नारायणपुर प्रवास के दौरान नारायणपुर वासियों को 127 करोड़ 83 लाख रूपये लागत के 101 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने इनमें से 72 करोड़ 8 लाख 25 हजार रूपए की लागत के 46 विकास कार्यों का लोकार्पण और 55 करोड़ 75 लाख रूपये की लागत के 55 विकासकार्यों का भूमिपूजन किया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री बघेल सामूहिक कन्या विवाह योजना में नव विवाहित 251 जोड़ों को उनके खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को चेक एवं उनकी जरूरत के समानों का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में अबूझमाड़ क्षेत्र के 500 किसानों को मसाहती पट्टे वितरित किये। श्री बघेल ने समाज कल्याण विभाग के 36 हितग्राहियों को श्रवण यंत्र, ट्रायसिकल, बैटरी चलित ट्रायसिकल, दिव्यांगजन विशिष्ट पहचान कार्ड, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनातर्गत राशि प्रदाय, रेशम विभाग के हितग्राहियों को 100 नग टसर बुनियादी रीलिंग मशीन, महिला रेशम कृमिपालन समूह को चेक वितरण, कृषि विभाग के हितग्राहियों को उड़द बीज, स्पेयर पंप, स्प्रिंकलर, श्रम विभाग के हितग्राहियों को भागिनी प्रसूति सहायता योजना और मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में सहायता राशि के चेक, मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांगजन सहायता योजना के चेक एवं 26 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र का वितरण किया।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नारायणपुर जिले जिन विकास कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें ब्रेहबेड़ा से मेटाडोंगरी वृहद पुल निर्माण लागत 7 करोड़ 67 लाख रूपए, जिला नारायणपुर में सर्किट हाउस का निर्माण कार्य लागत 5 करोड़ 89 लाख रूपए, सुलेंगा से तिरकानार 5 करोड़ 50 लाख रूपए, नारायणपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशासनिक एकेडमिक भवन निर्माण लागत 5 करोड़ 55 लाख रूपए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण अंतर्गत ग्राम महिमागवाड़ी से ताडोनार तक सड़क निर्माण लागत 3 करोड़ 20 लाख रूपए, स्कूलपारा से कोहकापारा लागत 3 करोड़ 33 लाख रूपए, नयापारा कुकड़ाझोर से खासपारा के लिए लागत 3 करोड़ 35 लाख रूपए सहित अन्य विकास कार्य शामिल है। इसी तरह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल नारायणुर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 24 करोड़ 72 लाख रूपए

इसी तरह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल नारायणुर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत 24 करोड़ 72 लाख रूपए की लागत से स्थापित होने वाली 36 सोलर आधारित नल-जल योजना, खोडगांव से चिचाडीपारा लागत 6 करोड़ 22 लाख रूपए, जल जीवन मिशन अंतर्गत सोलर ड्यूल पंपों की स्थापना कार्य लागत 5 करोड़ रूपए, मढोनार से कावानार लागत 3 करोड़ 82 लाख रूपए, 37 नवीन आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य लागत 2 करोड़ 5 लाख रूपए सहित अन्य विकास कार्यों का भूमिपूजन भी किया।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी

श्रीकंचनपथ न्यूज

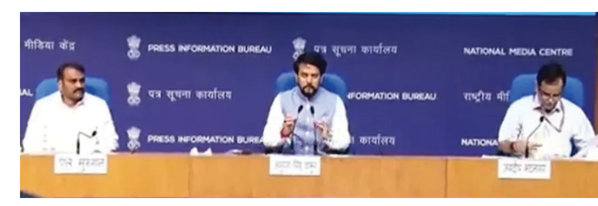

नई दिल्ली (पीआईबी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया (एफआरसी) के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

एफआरसी, सेबी की तरह, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन बहुपक्षीय एमओयू (आईओएससीओ एमएमओयू) का सह-हस्ताक्षरकर्ता है। हालांकि, आईओएससीओ एमएमओयू के दायरे में तकनीकी सहायता का प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन, प्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सूचना साझाकरण ढांचे को मजबूत करने में योगदान देने के अलावा, एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। तकनीकी सहायता कार्यक्रम से अधिकारियों को पूंजी बाजार, क्षमता निर्माण गतिविधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े मामलों पर परामर्श के माध्यम से लाभ होगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत भारत में प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए की गई थी। सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को विनियमित और बढ़ावा देना है। सेबी अधिनियम, 2002 की धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत खंड (आईबी); सेबी को बोर्ड के समान कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों, चाहे वे भारत में हों या विदेश में, से प्रतिभूति कानूनों के संबंध में उल्लंघनों की रोकथाम करने या जांच करने से संबंधित मामलों में जानकारी मांगने या जानकारी देने का अधिकार देता है, जो अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन है। भारत के बाहर किसी भी प्राधिकरण को कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, सेबी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के साथ एक व्यवस्था या समझौता या समझ विकसित कर सकता है। इस पृष्ठभूमि में, एफआरसी ने सेबी से आपसी सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है। अब तक, सेबी ने अन्य देशों के पूंजी बाजार नियामकों के साथ 27 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2006 में स्थापित, वित्तीय नियामक आयोग (एफआरसी) एक संसदीय प्राधिकरण है, जिस पर बीमा और प्रतिभूति बाजार एवं सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के प्रतिभागियों समेत गैर-बैंक क्षेत्र की निगरानी और विनियमन की ज़िम्मेदारी है। एफआरसी स्थिर और सुदृढ़ वित्तीय बाजार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। आयोग गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और मध्यवर्ती संस्थाओं, प्रतिभूति फर्मों तथा बचत और ऋण सहकारी समितियों का विनियमन करता है। साथ ही, यह व्यक्तिगत वित्तीय बाजार ग्राहकों (प्रतिभूति धारकों, घरेलू और विदेशी निवेशकों, और बीमा पॉलिसीधारकों) के अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

कैबिनेट ने गैर-परिचालन वाले कोयला खदानों को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने की मंजूरी दी

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली(पीआईबी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज कोयला मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बिना किसी जुर्माने (बैंक गारंटी की जब्ती) और बिना कोई कारण बताए गैर-परिचालन वाली खदानों को सरकार को वापस करने के लिए वन-टाइम विंडो देने का प्रावधान है।

इस फैसले से कई कोयला खदानें सरकार को वापस मिल सकती हैं, जिन्हें वर्तमान में आवंटन प्राप्त सरकारी पीएसयू विकसित करने की स्थिति में नहीं हैं या इस कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं है तथा वर्तमान नीलामी नीति के अनुसार उनकी नीलामी की जा सकती है। आवंटन प्राप्त सरकारी कम्पनियों को खदान वापस करने की स्वीकृत नीति के प्रकाशन की तिथि से तीन माह में कोयला खदानों को वापस करने का समय दिया जाएगा।

2014 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोयला ब्लॉकों को रद्द करने के बाद, ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में तात्कालिक व्यवधान को रोकने के लिए सरकार ने आवंटन के जरिये राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को कई रद्द किए गए कोयला ब्लॉक आवंटित किए थे। आवंटन का काम तेजी से किया गया और यह उम्मीद की गयी कि राज्य विद्युत उत्पादन कंपनियों को कोयले की आवश्यकता उन ब्लॉकों से पूरी हो जाएगी। राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देय राजस्व की हिस्सेदारी, प्रति टन के आधार पर तय की गयी, जबकि निजी क्षेत्र को इसके लिए बोली लगानी होती है। उस समय के कोयला ब्लॉकों के आवंटन के संदर्भ में, कोयला ब्लॉकों के परिचालन के लिए समय-सीमा की शर्तें बहुत कठोर थीं और सफल आवंटी या नामित प्राधिकारी के लिए छूट की कोई संभावना नहीं छोड़ी गई थी। कोयला खदानों के परिचालन में देरी के लिए दंड के परिणामस्वरूप विवाद हुए और अदालती मामले सामने आए।

दिसंबर-2021 तक, सरकारी कंपनियों को आवंटित 73 कोयला खदानों में से 45 खदानें गैर-परिचालन अवस्था में निष्क्रिय पड़ीं रहीं और 19 कोयला खदानों के मामले में, खनन कार्य शुरू करने की नियत तारीख पहले ही समाप्त हो चुकी है। विलंब की वजहें, आवंटियों के नियंत्रण से बाहर थीं, उदाहरण के लिए, कानून-व्यवस्था के मुद्दे; पहले घोषित किए गए क्षेत्र की तुलना में वन के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी; भूमि अधिग्रहण के खिलाफ भूस्वामियों का प्रतिरोध; कोयला संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में भूगर्भीय अप्रत्याशित तथ्य।

कोयला क्षेत्र, देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा की कुंजी है। अनुमोदन के तहत, अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला ब्लॉक जिन्हें जल्दी आवंटित किया गया था, को फिर से काम लायक बनाया जा सकता है।

कैबिनेट ने सभी सरकारी योजनाओं में फोर्टिफाइड चावल के वितरण को मंजूरी दी

श्रीकंचनपथ न्यूज

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों (यूटी) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-पीएम पोषण [पूर्ववर्ती मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएम)] और भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) में 2024 तक चरणबद्ध रूप से फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

चावल के फोर्टिफिकेशन की पूरी लागत (लगभग 2,700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष) जून, 2024 तक इसके पूर्ण कार्यान्वयन होने तक खाद्य सब्सिडी के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इस पहल के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन चरणों की परिकल्पना की गई है- चरण- ङ्क मार्च, 2022 तक पूरे भारत में आईसीडीएस और पीएम पोषण को कवर करना जो कार्यान्वयन के अधीन है। चरण- ङ्कङ्क उपर्युक्त चरण ङ्क के साथ-साथ मार्च 2023 तक सभी आकांक्षी और स्टंटिंग की समस्या से व्यापक रूप से प्रभावित जिलों (कुल 291 जिलों) में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याण योजनाएं (ओडब्ल्यूएस)। व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग राज्य सरकार/केंद्र-शासित प्रदेश, संबद्ध मंत्रालयों/विभाग, डेवलपमेंट पार्टनर्स, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों आदि जैसे सभी संबंधित हितधारकों के साथ इको-सिस्टम से जुड़ी सभी गतिविधियों का समन्वय कर रहा है।

।। न्यायालय नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.) ।।

// ईश्तहार //

रा.प्र.क्र. / / अ-20 (1) / वर्ष 2021-22

आवेदक राजकुमार होता आ. स्व. एल.एन. होता निवासी आमदी नगर हुडको भिलाई द्वारा एवं अन्य द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि आमदी नगर हुडको भिलाई में स्थित खसरा नं. 1/2, 2/2 का टु. भूखण्ड नं. एमआईजी 2/9 क्षेत्रफल 160 वर्गमीटर भूमि एल.एन होता को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आबंटित है। प्रश्नाधीन भूखंड में आवेदक का नाम फौती नामान्तरण/वसीयतनामा /दान पत्र के आधार पर नजूल अभिलेख में दर्ज है, जिस पर आवेदक काबिज है किन्तु पटटा प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा उक्त आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड का नवीन पटटा धारक / स्वयं के नाम पर निष्पादन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति / संस्था को दावा या आपत्ति हो, तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 25/4/22 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वत: या किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिस भू-खंड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 08/4/22 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर

नजूल जांच अधिकारी,
दुर्ग

YOGESH COMPUTER
Sale & Service
All Computer Peripherals & Repairing
Yogesh Sirame
Mo-9893342971
7748064280
Hardware, CCTV Camera, Networking, Software
Azad Chowk, Muktidham Raod, Ramnagar, Supela, Bhilai
e-mail: sirameyogesh@gmail.com

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

GREEN COMPUTER
Sales, Services, Repairs
Laptop Repairing
Printer
Desktop
7/2, Dakshin Gangotri, Supela, Bhilai
0788-4083385

Y Fitness
• Gym Servicing
• Gym Equipment & Accessories Available
• Home Treadmill & Gym Service Available
start 17500/-
Bajaj Finance Available
Shop No. 10, 14, Block, Street No.-7 Dakshi1 ga1gotri, Supela, Bhilai Chhattisgarh
Facebook id - Protein Planet Bhilai
9098981555

मथुरावासी चाट सेंटर
शादी एवं पार्टियों के आर्डर लिए जाते हैं।
9893283525
जैन पान ठेला के सामने आकाश गंगा सुपेला

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
कवर ही कवर
I-PHone,Samsung, MI, Oppo, Vivo, Nokia, HTC, Blue tooth Charger, Power Bank, Ear Phone, BT. Speakar
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

दास गार्मेन्ट्स
जींस, शर्ट, टी-शर्ट, फ्राक सूट, फ्राक, फैंसी सलवार सूट एवं किट्स वियर,अंडर गारमेन्ट्स, गाउन के लेटेस्ट कलेक्शन
एक बार अवश्य पधारें
गणेश मार्केट, गुरुद्वारा, रोड सुपेला, भिलाई, 7828248067

Ashok JEWELLERY
Gifts • Toys • Cosmetics
Perfumes • Sia Jewellery
Beside Parakh Jewellers, Akash Ganga, Supela, Bhilai
Hello: 0788-4052727
Mukesh Jain 9009959111
Rishabh Jain 8103831329

14 साल के बच्चे का काट दिया सिरः इतनी जोर से किया वार कि कुल्हाड़ी सिर में धंसी, महुआ बीनने को लेकर हुआ था विवाद

कांकेर (ए)। कांकेर में 14 साल के बच्चे की निर्ममता से हत्या कर दी गई। महुआ बीनने के विवाद में खेत के पूर्व मालिक ने बच्चे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वार इतना तेज था कि कुल्हाड़ी बच्चे के सिर को चीरती हुई अंदर धंस गई। आसपास के लोगों ने बच्चे को खून से लथपथ पड़ा देखा तो परिजनों को सूचना दी। हालांकि जब तक बच्चे को अस्पताल ले गए, उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

परतापुर क्षेत्र के गांव पीवी 124 में निवासी 14 साल का बच्चा दीनबंधु सरकार पुत्र दीपक सरकार घर से करीब आधा किमी दूर गांव के बाहर महुआ बीनने के लिए रोज जाता था, लेकिन खेत का पुराना मालिक मिथुन चढ्ढा (35) उसे मना करता। बताया जा रहा है कि दीनबंधु गुरुवार को भी महुआ बीनने के लिए गया था, तभी वहां मिथुन पहुंचा और बच्चे को देख भड़क गया। आरोप है कि उसने अपने पास रखी कुल्हाड़ी से दीनबंधु के सिर पर वार कर दिया।

कुल्हाड़ी निकालते ही फूट पड़ी खून की धार

वार इतना घातक था कि कुल्हाड़ी बच्चे के सिर में धंस गई। बच्चा वहीं खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वहां से जा रहे लोगों ने बच्चे को देखा तो सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने मौके पर पहुंच बच्चे के सिर से कुहाड़ी निकाली तो खून की धार फूट पड़ी। वह उसे इलाज के लिए पखांजूर अस्पताल लेकर भागे, लेकिन हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई।

सनकी है हत्यारोपी, खेत बेचने के बाद पेड़ पर जताता था हक

बच्चे का हत्यारोपी मिथुन वारदात के बाद भागकर अपने घर में छिपा था। पुलिस को हत्या की सूचना मिली तो वह जांच में जुट गई। इस बीच पता चला कि मिथुन ने ही बच्चे की हत्या की है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सनकी किस्म का है। छोटी-छोटी बातों पर वह लोगों से मारपीट करता था। जिस खेत में महुआ बीनने को लेकर विवाद हुआ, वह भी आरोपी बेच चुका था, लेकिन पेड़ पर अपना हक जताता था।

तीन माह में 14 हत्याएं, इसमें 11रंजिश में

पिछले तीन माह में जिले के अलग-अलग थाना इलाकों में हत्या के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 3 हत्याएं ही नक्सलियों ने की है। जबकि बाकि 11 हत्याएं आपसी रंजिश में रिश्तेदार और ग्रामीणों ने ही की है। इसमें से अधिकांश हत्याएं छोटे और मामूली विवाद में सगे भाई व पुत्र ने की है। वहीं कुछ हत्याएं पड़ोसी से रंजिश के चलते की है। सबसे गंभीर हत्याओं में शामिल दुधावा के मुसुरपुट्?टा की घटना है। जिसमें एक महिला ने अपने दो छोटे छोटे बच्चों की गला घोट कर मार डाला था।

पेड़ से टकराई कार, एक की मौत

हादसे के बाद गाड़ी में ही फंस गया युवक, 2 गंभीर रूप से घायल

रायपुर (ए)। रायपुर-जगदलपुर नेशनल हाईवे 30 में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डस्टर कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में वाहन चालक एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। दोनों पति- पत्नी को कोंडागांव जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में जिस युवक की मौत हुई है उसकी महज 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। हादसा कोंडागांव सिटी कोतवाली क्षेत्र में हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, केशकाल का रहने वाला लोकेश पिल्ले अपनी डस्टर वाहन से महासमुंद के रहने वाले पति-पत्नी रिजवान और सियोना को जगदलपुर उनके रिश्तेदार के घर छोड़ने जा रहा था। इस बीच कोंडागांव-जगदलपुर के बीच जोबा के पास मोड़ में कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। बताया जा रहा है कि तेज बारिश होने की वजह से कार का ब्रेक नहीं लगा और हादसा हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के पूरे परखच्चे उड़ गए।

वाहन चालक लोकेश पिल्ले करीब एक घंटे तक वाहन में ही फंसा रहा। इस मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने घायल पति-पत्नी को तो वाहन से तो बाहर निकाल लिया, लेकिन लोकेश को नहीं निकाल पाए। दोनों पति पत्नी को अस्पताल भिजवाया गया। राहगीरों ने हादसे की सूचना कोंडागांव सिटी कोतवाली के जवानों को दी। मौके पर पहुंचे जवानों ने JCB की मदद से कार को निकाला। फिर कटर मशीन से कार में फंसे युवक लोकेश को निकाला गया। जिसने दम तोड़ दिया था।

एक महीने पहले ही हुई थी शादी

केशकाल के रहने वाले लोकेश पिल्ले की महज 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। लोकेश की मां और बड़ा भाई-भाभी भी हैं। बताया जा रहा है कि केशकाल में अपने परिचित परिवार के बेटी-दामाद को छोड़ने के लिए यह अपनी निजी वाहन से ही जगदलपुर आ रहा था। लेकिन, बीच रास्ते सड़क हादसे में युवक की जान चली गई।

खास-खबर

पत्नी की मौत के गम में पति ने की खुदकुशीः 3 महीने पहले बीवी ने दी थी जान, तब से उदास था, अब उसकी ही चुनरी से लगाई फांसी

भिलाई। दुर्ग जिले में दो मासूम बच्चों के सिर से पहले मां का साया छिना। इसके बाद पिता ने भी खुदकुशी करके उन्हें अनाथ कर दिया। पत्नी की मौत से दुखी पति ने खुर्सीपार स्थित अपने घर में शुक्रवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। खुर्सीपार टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कबीर मंदर के पास रहने वाले पिंटू चौधरी (28 साल) ने अपने घर में गुरुवार व शुक्रवार की रात फंसी लगा ली। सुबह जब मोहल्ले के लोगों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जब मौके पहुंची और लोगों से बात की चौंका देने वाली सच्चाई पता चली। लोगों ने बताया कि तीन महीने पहले पिंटू की पत्नी ने इसी घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। पिंटू के दो छोटे-छोटे बच्चे हैं। पत्नी की मौत के बाद पिंटू काफी दुखी रहता था। वह न तो घर और न ही बच्चों का ध्यान दे पाता था। इसके चलते दोनों बच्चों को उसके नाना नानी अपने साथ ले गए। घर में पिंटू अकेला था। लोगों से भी अधिक बात नहीं करता था। अचानक उसने अपने घर में पत्नी की चुनरी के सहारे फांसी लगा लिया। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

कम्प्यूटर आपरेटर पर शराब के नशे में धुत बदमाशों ने किया जानलेवा हमला

रायपुर (ए)। राजधानी रायपुर में रास्ता रोककर सरकारी विभाग के कम्प्यूटर आपरेटर पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। जिसकी शिकायत पीड़ित ने अभनपुर थाने में की है। बताया जा रहा है कि वे अपने मामा के यहां गातापार में शादी समारोह में शामिल होने गया था। शादी सम्पन्न होने के बाद वापस आ रहे थे, तभी गांव के योगेन्द्र घृतलहरे एवं अन्य दो साथी शराब के नशे में धुत होकर जबरन गाली गलौज करने लगे। जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और हाथ मुक्का से मारपीट की घटना को अंजाम दिया।

हड़ताल में शामिल संविदा बिजलीकर्मी के बाइक को पीछे से एसयूवी ने मारी टक्कर, एक की मौत, दो घायल

रायपुर (ए)। रायपुर में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे संविदा बिजली कर्मचारियों में से एक की गुरुवार देर रात लालपुर ओवरब्रिज के नीचे सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसके दो साथी घायल हो गए। इस हादसे की जानकारी मिलने पर शुक्रवार को हड़ताल में बैठे सैकड़ों संविदाकर्मी आंबेडकर अस्पताल स्थित चीरघर के सामने धरने पर बैठ गए। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने समझा-बुझाकर वापस धरना स्थल भेजा।

जानकारी के मुताबिक रायपुर में चल रही हड़ताल में शामिल जनवासी बाजारपारा, कोंडागांव निवासी बनीराम बघेल (28) गुरुवार को अपने साथी नवरतन कोर्राम, निवासी मांडखडी, परसगांव की बाइक क्रमांक सीजी 19 बीएम 7132 से प्रेमलाल के साथ बैठकर माना इलाके में रह रहे रिश्तेदार से मिलने गया था। वहां से रात साढ़े 10 बजे तीनों वापस लौट रहे थे।

लालपुर ओवरब्रिज के नीचे जैसे ही पहुंचे, पीछे से तेज गति से आ रही अज्ञात फार्च्यूनर कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर सवार बनीराम समेत तीनों युवक जमीन पर गिर पड़े और तेज रफ्तार फार्च्यूनर बनीराम को कुचलते हुए आगे निकल गई। साथियों ने बताया कि हम लोग बनीराम को बचाने की कोशिश करते हुए उन्हें अस्पताल लेकर गए, मगर उनकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने तड़पते हुए हमारी आंखों के सामने ही दम तोड़ा। नवरतन कोर्राम की शिकायत पर टिकारापारा पुलिस ने अज्ञात फार्च्यूनर कार के खिलाफ अपराध कायम कर लिया है।

सड़क हादसे में एक साथी की मौत होने की जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जिलों से हड़ताल पर बैठे संविदा विद्युतकर्मी शुक्रवार दोपहर अचानक आंबेडकर अस्पताल के पीछे पोस्टमार्टम करने की जगह के बाहर जमा हो गए। इन संविदा कर्मचारियों को देखकर पुलिस भी सकते में आ गई। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों ने कर्मचारियों से बातचीत की। दरअसल साथी की मौत से दुखी कर्मचारी इसी जगह में आंदोलन करने की तैयारी में थे। संविदा विद्युत कर्मचारी बेहद गुस्से में थे।

पिता बीमार है कहकर ले गया और किया रेप, आरोपी गिरफ्तार

कोंडागांव (ए)। कोंडागांव जिले में एक युवक ने नाबालिग का रेप किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक नाबालिग को उसके पिता बीमार है कहकर बाइक से घर लेकर जा रहा था। इस बीच, बीच रास्ते में जंगल में मौके का फायदा उठाकर नाबालिग से रेप कर दिया। युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला जिले के विश्रामपूरी थाना क्षेत्र का है।

पुलिस के अनुसार, 5 अप्रैल को नाबालिग अपने परिजनों के साथ पुलिस थाना आई। जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि 19 फरवरी को नाबालिग मुरूमडिही ईंट भट्टी के पास वो खाना खाकर सो रही थी। इस बीच गांव का ही युवक धनेश यादव अपनी बाइक से आया, और पिता बीमार है कहकर जबरदस्ती बाइक में बिठाकर ले गया। वहीं बीच रास्ते में जंगल में दुष्कर्म किया।

इस घटना के बाद नाबालिग काफी डरी हुई थी। इसलिए उसने अपने परिजनों को अपने साथ हुए अनाचार के बारे में नहीं बताया। जब घर में नाबालिग लगातार डरी सहमी और शांत रहने लगी तो परिजनों ने पूछा। जिसके बाद नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। वहीं परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

लम्बे संघर्ष के बाद मिली जीतः 60 साल बाद मिला न्याय, हाईकोर्ट ने भूमि अधिकार को किया सुरक्षित

बिलासपुर (ए)। 60 साल से अपनी जमीन के लिए संघर्षरत व्यक्ति को न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के भूमि हक को सुरक्षित करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस राजेंद्र चंद्र सिंह सामंत की सिंगल बेंच में हुई। मो. अमान रायपुर सदर बाजार के रहने वाले हैं। उन्होंने अधिवक्ता कमरुल अजीज के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें बताया कि याचिकाकर्ता के पिता शेख रहमान जो शेख रहिम के बेटे हैं ने 15 अप्रैल 1947 में कोटा में खसरा नंबर 19/1 और 159/1 में कुल 9.89 एकड़ कृषि भूमि खरीदने के लिए समझौता किया।

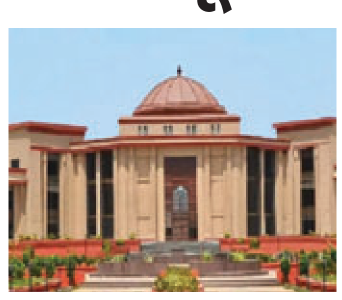

इसके बाद 3 फरवरी 1951 को जमीन की बिक्री अपने नाम से करवा ली और तब से वह उस भूमि पर काबिज हैं। इसी बीच जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत अवैधानिक रूप से उनकी जमीन को शासकीय घास भूमि के रूप में दर्ज कर दिया गया। इसके विरुद्ध याचिकाकर्ता के पिता ने कलेक्टर के समक्ष अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर उन्मूलन करने की मांग की।

जिस पर 23 मई 1964 को कलेक्टर ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में स्थानांतरण शून्य नहीं है। इस पर आयुक्त ने स्वत: संज्ञान लेकर मामले को सुना और 3 जुलाई 2002 को 1964 में पारित आदेश की पुष्टि की। इसके बाद शासन ने कहीं और अपील नहीं की तो इस आदेश ने अंतिम रूप ले लिया। इसके बाद याचिकाकर्ता के पिता ने तहसीलदार को अपने नाम पर भूमि दर्ज करने का आवेदन दिया।

जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि यह भूमि सरकारी शीर्ष के तहत घास भूमि दिखती है। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्री विलेख आज तक वैध है, इसलिए प्रतिवादी अधिकारी याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन से इनकार नहीं कर सकते। इसलिए आदेश को रद्द करने की मांग की गई। मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश को रद्द कर अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा।

उप मंडल अधिकारी ने खारिज की, अतिरिक्त आयुक्त ने स्वीकार किया

उप-मंडल अधिकारी के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे 11 फरवरी 2011 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (2) के तहत अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष अपील दायर की गई। अपील को 4 जनवरी 2013 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी व तहसीलदार के आदेशों को खारिज कर दिया गया। इस पर राज्य शासन ने राजस्व बोर्ड के समक्ष संशोधन की अर्जी प्रस्तुत की। इस पर राजस्व बोर्ड ने 19 दिसंबर 2017 को पुनरीक्षण की अनुमति दी। साथ ही अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित 4 जनवरी 2013 के आदेश को रद्द कर दिया।

अब दुकानों में भी डस्टबिन रखना अनिवार्य, नही तो होगी कार्रवाई

रायपुर (ए)। राजधानी रायपुर की दुकानों में अब डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है।नगर निगम प्रशासन ने आदेश जारी कर अफसरों को निर्देश दिए हैं कि जिन दुकानों में डस्टबिन नहीं मिल रहे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करे। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। हर दुकान में पन्नी, पालिथिन रखने पर भी नगर निगम की टीम जुर्माना कर रही है।

नगर निगम की टीम पिछले कई दिनों से लगातार दुकानों, ठेले, सब्जी बाजार,गोलबाजार में छापेमारी कर प्रतिबंधित पालिथीन की जब्ती कर रही है।निगम जोन पांच की टीम ने चंगोरा बाजार और गोल चौक इलाके में छापा मारा। 20 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर दुकानदारों पर 2650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं जोन दो की टीम ने देखा कि 17 दुकानों में कोई डस्टबिन नहीं है। 17 करोबारियों पर 3150 रुपये जुर्माना लगाया गया। यह छापेमार कार्रवाई देवेंद्र नगर इलाके में की गई। सभी 17 दुकानदारों को निगम की टीम ने कड़ी चेतावनी दी है, और दुकान में डस्टबिन रखने को कहा है।

नगर निगम रायपुर ने कारों में भी डस्टबिन अनिवार्य कर दिया है। महापौर एजाज ढेबर के निर्देश के बाद से गाड़ियों के सभी शो रूम नई कारों के साथ डस्टबिन दे रहे हैं। नगर निगम का निर्देश है कि कारों में डस्टबिन हमेशा हो और कचरा इसी में डाला जाए, बाद में कूड़ा किसी सही जगह पर फेंका जाए। रायपुर में डस्टबीन को लेकर इस तरह की अनिवार्यता पहली बार है। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में रायपुर को देश का सबसे साफ शहर बनाने की कवायद जारी है।

आदित्य ड्राई क्लीनर्स
Pick & Drop Service Available (Terms & Condition Applied)
98271-90875
99938-08453
75877-57239
सोफा पर्दा कारपेट सीटकवर लेदर जैकेट टेड्डी वियर शू
सभी प्रकार के कपड़ों का आधुनिक तकनीकी से ड्राईक्लीन किया जाता है।
Shop NO.-105, "A" Market, Sector-6, Bhilai (C.G.)

Galaxy Granite
रायपुर से कम दामों में
WholeSaler & Retailer
All Type Of Tiles : Wall Tiles, Floor Tiles, Granite Sanitary & Null Fitting
सभी प्रकार के टाईल्स और ग्रेनाईट मिलने का एक मात्र स्थान
कोई भी टाईल्स लेने से पहले एक बार अवश्य पधारे...
Raja Steel Traders, Krishna Talkies, Road, Side of ZEE Maha Sale, Risali, Bhilai - 490006
K.K. Soni - 77479-88643, 9109509095

House of tiles
Complete Range of Tiles, Marble And Granite in One Shop
KESWANI TILSE
कृष्णा टाकिज रोड, राजा स्टील के सामने, रिसाली, भिलाई (छ.ग.)
Mo. _- 82349 - 21000

राकेश ट्रेडर्स
विगत 6 वर्षो से यह दुकान पानी टंकी के सामने स्थानांतरित हो गई है।
Dealers
Marbles, Grinight, Black Stone, Nano & Double Charge Verified Tiles Digital Wall & Floor Tiles Cement Coloru etc.
रायपुर रेट पर माल उपलब्ध
Rakesh Sahu 9302443750, 9907127357
Krishna Talkies Road, Beside Hariom Furniture, Risali, Bhilai - 490006

भिलाई मसाला उद्योग
शुद्ध कुटे हुए मसाले,पापड़, अचार, बड़ी, जड़ी-बूटी, जचकी का सामान इत्यादि
128, ए- मार्केट, सेक्टर-6, भिलाई, फोन. 2284508, मो. 9826137766

मिस एंड मिसेस
लेडिस वेयर
• गाऊन
• ब्रा. पेन्टी
• नाईटी
• ब्लाउज
सभी प्रकार के अंडरगारमेंट्स की विशाल रेंज
शॉप नं-113, सेक्टर-6, ए मार्केट भिलाई

दुल्हन बैंगल्स & फैंसी
RUPESH KUMAR
Mob.-9840760388
7987759030
Specialist : Wedding mix match bangles, Glass bangle, Plastic bangle. Saree pin, Bindi, Rubber Band. Bracelet, Butter Fly, Ear ring and many more
कृष्णा टाकिज रोड, विजय भवन के पास, रिसाली, भिलाई
जलाराम मिष्ठान के सामने, इंदिरा मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

माँ दुर्गा ज्वेलर्स
सोने एवं चांदी के आभूषणों विक्रेता
उचित ब्याज में गिरवी रखी जाती है
शॉप नं. 69, सी-मार्केट सेक्टर-6, भिलाई
मो. 9424124911

भारतीय बैग हाउस
VIP happy journey
AMERICAN TOURISTER
फैंसी स्ट्राली, स्कूल बैग, ऑफिस बैग, सफर बैग, लेपटॉप बैग, फैंसी छतरी, रेनकोट इत्यादि के विक्रेता
कृष्णा टाकीज रोड, बैंक ऑफ बडौदा के बाजू में रिसाली भिलाई, संजय गुप्ता : 93003-77572

खास - खबर

गौठान में हो रही गतिविधियों का निरीक्षण किया दुर्ग संभागायुक्त ने

दुर्ग। जिले के गौठान की व्यवस्था देखने के लिए नोडल अधिकारी गौठानों का भ्रमण कर रहे है। राज्य शासन के निर्देशानुसार दुर्ग जिले के गौठान में होने वाली गतिविधियों को देखने के लिए आज दुर्ग संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने विभिन्न ग्राम पंचायतों का भ्रमण कर गौठान की जमीनी हकीकत देखी। उन्होंने आज रिसामा एवं मतवारी गौठान में पशुधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन करते हुए कार्यरत महिला स्व सहायता समूह एवं ग्राम गौठान समिति के सदस्यों से उनके कार्यो की जानकारी ली। इस दौरान गोबर खरीदी तथा खाद निर्माण की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हुए गौठान को आजीविका केंद्र के रूप में सतत आगे बढ़ाने हेतु अनेक सुझाव दिए। श्री कावरे ने गौठान के सभी गतिविधियों का निरीक्षण करते हुए समूह के सदस्यों से कहा कि वे अपने आय -व्यय की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें, गौठान में उपलब्ध स्थानों का बेहतर उपयोग करते हुए आजीविका के नए साधन विकसित करें। रिसामा गौठान में लक्ष्मी महिला स्व सहायता समूह ,शीतला महिला स्व सहायता समूह , श्री श्री महिला स्व सहायता समूह की दीदियों से वर्मी खाद उत्पादन की चर्चा की गई। उनके द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष कुल 606 क्विंटल खाद का निर्माण किया गया जिसको विक्रय कर तीनो समूह को क्रमश- 53000 रुपये, 33000 रुपये और 39000 रुपये इस प्रकार कुल सवा लाख रुपये से अधिक की आमदनी अर्जित की। इस पर संभागायुक्त ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महिलाओं का उत्साहवर्धन किया ।साथ ही महिला समूह द्वारा तैयार की गई बाड़ी को देखकर संभागायुक्त ने ऐसे अन्य आजीविका संवर्धन के कार्य को करने हेतु सुझाव देते हुए शुभकामनाएं दी। निरीक्षण के दौरान मतवारी गौठान में वर्मी खाद, मुर्गी पालन, और मछली पालन के कार्य देखा गया। मतवारी के बिहान समूह की दीदियों द्वारा वर्मी खाद का उत्पादन किया गया। अंकुर महिला स्व सहायता समूह द्वारा 42 हजार रुपये और अर्पणा महिला स्व सहायता समूह द्वारा 19 हजार रूपये इस प्रकार 61 हजार रुपये की कमाई हुई।

महापौर नीरज पाल का फैसला व आयुक्त की मेहनत अब धरातल पर दिखने लगी

श्रमिक बस्ती में पेयजल समस्या के समाधान के लिए ग्राउंड लेवल पर उतरा निगम प्रशासन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। निगम क्षेत्र में रोज सुबह एक घंटा विद्युत प्रवाह बंद किए जाने का अनुकूल असर अब दिखने लगा है। इससे शहर के सभी जोन के वार्डों के नलों में प्रेशर बढ़ा है और अंतिम छोर के नलों से भरपूर पानी की आपूर्ति हो रही है। महापौर नीरज पाल के निर्देश के बाद आयुक्त प्रकाश सर्वे व उनकी टीम की मेहनत धरातल पर कारगार साबित होने लगी है।

भीषण गर्मी में पेयजल संकट से निपटने के लिए भिलाई निगम प्रशासन ने अभी से कमर कस लिया है और इसके लिए पूर्ण रूप से अपनी सक्रियता बढ़ा दिया है। महापौर नीरज पाल ने गर्मी के दिनों में वार्डों में पेयजल का संकट न हो, हर परिवार को पर्याप्त पानी मिले। जलापूर्ति के समय कोई टुल्लू पंपों का उपयोग न कर सके।

इसके लिए लोगों की मांग एवं जल कार्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर सुबह एक घंटा विद्युत प्रवाह बंद कराने का निर्देश दिया था, ताकि सभी को पर्याप्त पानी मिल सके। झुग्गी बस्तियों के घरों में पानी लेन के लिए लोग टुल्लू पंप का उपयोग कर पाइपलाइन से पानी खींच ले रहे थे। इससे आसपास व अंतिम छोर के घरों तक नलों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसकी लगातार शिकायत वार्ड के लोगों से मिल रही थी। महापौर नीरज पाल के निर्देश और जन शिकायतों का निराकरण करने आयुक्त प्रकाश सर्वे ने आज सुबह मॉर्निंग विजिट में जोन 3 के सुंदर नगर वार्ड क्रमांक 32 के श्रमिक बस्तियों में सुबह 6 बजे पेयजल आपूर्ति का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान बस्ती के लोगों से उन्होंने चर्चा की। वार्ड की महिलाओं ने बताया कि जगह-जगह बीएसपी द्वारा बिछाई पुरानी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। आयुक्त सर्वे ने मोहल्ले वासियों को आश्वस्त किया कि अमृत मिशन फेस-दो के तहत पाइपलाइन बिछाने की कार्ययोजना बनाई गई है, शीघ्र विभागीय प्रक्रिया पूर्ण कर इस पर काम किया जाएगा।

आयुक्त ने जोन आयुक्त येशा लहरे को निर्देशित किया कि टुल्लू पंप का उपयोग न हो, इसकी लगातार निगरानी करते रहे। वहीं सफाई निरीक्षक वीरेंद्र बंजारे को वार्ड में बिखरे कूड़े-कचरों व नालियों की सतत सफाई करवाने कहा। जोन आयुक्त को जिन स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां टैंकरों से भी पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन 3 आयुक्त येशा लहरे, सब इंजीनियर कृष्ण कुमार जंघेल, निरीक्षक वीरेंद्र बंजारे, बबलू राम साहू, श्याम ठाकुर व वेंकट आदि कर्मचारी भी मौजूद थे।

जोन 4 क्षेत्र के सेक्टर 11 बालाजी नगर, सुभाष नगर, बापू नगर, सोनिया नगर व गौतम नगर में लो प्रेशर के कारण पानी नहीं पहुंच पा रहा था। अब एक घंटा विद्युत कटौती होने के बाद सभी के घरों तक पर्याप्त पानी पहुंच पा रहा है। उल्लेखनीय है कि जलापूर्ति के समय अधिकतर लोगों द्वारा टुल्लू पंप से पानी खींच लिया जाता था।

चैत्र नव रात्रि के पर्व पर नौ दिन का भजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई श्रीमती मंजू वोरा

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। आर्य नगर दुर्ग की महिलाओं द्वारा ट्विकल किड्स स्कूल में नौ दिन का भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर पूजा पाठ में शामिल हो रही है।

इस कड़ी में आज मुख्य अतिथि के रूप में शहर विधायक अरुण वोरा की धर्मपत्नी श्रीमती मंजू वोरा शामिल होकर मौजूद सभी महिलाओं को चैत्र नवरात्रि पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दी, डॉ. मानसी गुलाटी ने भजन गाकर लोगों का दिल जीत लिया, समाजसेवी श्रीमती नीलु सिह एवं ब्रांड एम्बेसडर नविता शर्मा ने अपने नृत्य कला से माता जी के भजन का आनंद लिए

अतिथि के स्वागत की कड़ी में मंच संचालन श्रीमती नविता शर्मा ने किया, मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू वोरा को चुनरी ओढा कर मंडली की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती पदमा दीक्षित ने स्वागत किया, वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती नीलु सिह का स्वागत स्कुल की प्राचार्य ज्योति तनना के द्वारा चुनरी ओढा कर किया गया

भजन में श्रीमती मंगला , शास्त्री,श्रीमती नीरु आनंद, श्रीमती उषा आनन्द, श्रीमती आशिमा, श्रीमती हीरा गौरी , तारा , श्रीमती मंजू पुरोहित, श्रीमती इंदु बेन , श्रीमती निर्मला राठौर, कमला ,इंदु सोनछत्रा, सुशीला बेन, दमयंती बेन आदि बहुत संख्या में महिलाएं उपस्थिति रहे।

विधायक व महापौर ने शीतल जल उपलब्ध कराने प्याऊ घर का किया शुभांरभ

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। पुराना बस स्टैंड के पास सत्य साईं सेवा समिति द्वारा गर्मी के समय राहगीरों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ घर का विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने समाजसेवी सत्य साईं सेवा समिति के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक अरुण वोरा ने कहा गर्मी के समय राहगीरों के लिए प्याऊ आरंभ करने का चलन रहा है।

इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाएं बेहतर काम करती हैं। विधायक अरुण वोरा व महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि गर्मी में परेशानी केवल नागरिकों को परेशान नहीं करता। गर्मी के मौसम में पक्षी भी पेयजल के लिए परेशान रहती हैं। इसके लिए उन्होंने नागरिको से अपील कर कहा कि अपने घर के आंगन,छत में और

दीवारों में पक्षियों के लिए पानी से भरे सकोरे रखें। प्याऊ घर स्थापना के दौरान मौजूद थे सत्य साई सेवा समिति, दुर्ग के समिति के सदस्यों के उपस्थिति में बी.पी. पांडेय जी, आर.के. तिवारी जी, हरीश चंद्र ठाकुर जी,शंकर लाल चंद्राकर जी, वी श्रीनिवास राव,नंदन दुबे जी और देव कुमार साहू,नारायण ठाकुर जी के उपस्थिति रही!महिलाओं में श्रीमती मीना पांडेय, कु. अनुश्री गीते और कु. वी सुहासिनी भी अपनी उपस्थिति दिए थे।

मेरा सेल, मेरा गौरव पर फिल्म निर्माण में योगदान देने वाले युवा कठपुतली कलाकार सम्मानित

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के अनुसंधान एवं नियंत्रण प्रयोगशाला में कार्यरत कर्मचारी विभाष उपाध्याय द्वारा कठपुतली शो के मंचन के लिये कठपुतली मंचन की तकनीक में दस युवा कठपुतली कलाकारों को प्रशिक्षित किया था।

भिलाई इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क विभाग द्वारा निर्मित फिल्म के लिए कठपुतली शो के मंचन हेतु इनको प्रषिक्षित किया गया था। जनसंपर्क विभाग द्वारा विभाष उपाध्याय तथा उनकी टीम को श्रेष्ठ प्रदर्षन के लिए सम्मानित

किया गया। सेल गौरव दिवस के अवसर पर भिलाई इस्पात संयंत्र ने 'मेरा सेल, मेरा गौरव' पर एक फिल्म का निर्माण एक अलग अंदाज में किया था।

मेरा सेल, मेरा गौरव विषय पर स्क्रिप्टिंग के बाद कला मंदिर में कठपुतली शो का मंचन किया गया और इसे फिल्माया गया था। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के विभिन्न पहलुओं को जिनमें भिलाईवासियों को गर्व है उसे कठपुतली शो के पात्रों द्वारा वर्णन के साथ समाहित किया गया है। एक लाइव शो में सेल की अन्य इकाइयों द्वारा तैयार की गई फिल्मों के साथ-साथ भिलाई के जनसंपर्क विभाग द्वारा संपादन के बाद फिल्म को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र की फिल्म को अद्वितीय और अच्छी तरह से विषय को प्रस्तुत करने के लिए बहुत सराहा गया था। विभाष उपाध्याय के निर्देशन में स्टील सिटी भिलाई के बाहरी क्षेत्रों में रहने वाले युवक जितेंद्र साहू, चंद्रशेखर बंजारे, सुजीत कुमार यादव, लोकेश वर्मा, आकाश वर्मा, गजानंद यादव, दीपक साहू, प्रहलाद कामडे, राजीव अग्रवाल और दिगेश्वर वर्मा ने कठपुतली शो में योगदान दिया। जनसंपर्क विभाग के महाप्रबंधक एस के दरिपा तथा वरिष्ठ प्रबंधक द्वय सत्यवान नायक व जवाहर बाजपेयी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दस युवा कठपुतली कलाकारों और उनके निदेशक उपाध्याय को प्रमाण पत्र, टोकन तथा उपहार से सम्मानित किया गया।

10 लाख की लागत से हुडकों में बनेगा बैडमिंटन एस्ट्रो टर्फकोर्ट

विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल की पहल से जल्द होगा काम शुरु

विधायक प्रतिनिधि व पीडब्ल्यूडी प्रभारी एकांश बंछोर ने किया भूमिपूजन

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। हुडको में ए मार्केट के पास मुख्य सड़क से लगे हुए मैदान में बैडमिंटन एस्ट्रो टर्फ कोर्ट के निर्माण किया जाएगा। करीब 10 लाख की लागत से भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल की पहल से क्षेत्रवासियों की मांग पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को भूमिपूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में विधायक देवेंद्र यादव एवं महापौर नीरज पाल के निर्देश पर नगर पालिका निगम भिलाई के राजस्व विभाग के प्रभारी सीजू एंथोनी एवं लोक कर्म विभाग के प्रभारी एकांश बंछोर मुख्यअतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जहां पूरे विधी विधान से भूमिपूजन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित हुडको वासियों ने विकास की गति को निरंतर बनाए रखने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जावेद खान,अरूण अग्रवाल, दानेशवरी साहू,जी एस सिंह, विनोद अमीन,पी श्रीनीवास,अनील पाटील, रविशंकर सिंह, श्यामल राय,अनील झा,सी अनील, सैम्यूल डेविड, पीके नंदी,मोहन राव, मुकेश दुग्गल, सतीश श्रीवास्तव, के मधुलाल वृंदावन पंडा,एस बाजी, पल्लव सोम, नेमीचंद शर्मा,संदीप डोंगरे, दिनेश शर्मा, मुकेश देशमुख,शंभू सिंह,उमेश तिवारी, प्रमोद शाह, राजन पाटील, संजय सराफ,एन एस काले,करण कनौजिया, अनिता तिवारी, पार्वती देशमुख, पुष्पलता साहू, मंजुलता अग्रवाल,सांई किरण, गोविंद अग्रवाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

व्यापारियों ने प्लास्टिक का उपयोग बंद करने दोहराया संकल्प

भिलाई शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने चलाया जा रहा प्लास्टिक मुक्त अभियान

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। प्लास्टिक मानव जीवन के लिए फायदा कम, अपितु हानिप्रद ज्यादा होता है। इसके रोकथाम के लिए न केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही, बल्कि प्रादेशिक व स्थानीय स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई नगर निगम प्रशासन द्वारा भी जनता को जागरूक करने के लिए पूर्ण रूप से जतन किए जा रहे हैं। निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में सिंगल यूज प्लास्टिक को नकारने के लिए वृहद रूप से जन जागरूकता अभियान 31 मार्च से चलाया जा रहा है।

महापौर नीरज पाल के निर्देश व निगमायुक्त प्रकाश सर्वे के नेतृत्व में आज 8 मार्च को रविशंकर शुक्ल मार्केट व टी मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान महिलाओं ने बैनर के माध्यम से लोगों को संदेश दिया कि अब प्लास्टिक को नकारो। वहीं इसके माध्यम से यह भी बताया गया कि प्लास्टिक को हटाने से मानव जीवन को बचाया जा सकता है। महापौर नीरज पाल ने समूह की महिलाओं द्वारा छेड़े इस अभियान की तारीफ की।

आज समूह की महिलाओं के अतिरिक्त बच्चों-बूढ़ों सहित सभी वर्गों को इसका अभिन्न हिस्सा बनने की जरूरत है। तभी वास्तविक में यह अभियान सच्चे अर्थों में सफल हो सकेगा। उन्होंने निगम क्षेत्र की आम जनता व व्यापारियों से अपील की है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पूरी तरह से बहिष्कार करें।

इसकी जगह कपड़ायुक्त कैरी बैग को अधिक प्रचलन में लाएं। इसके बहिष्कार से क्षेत्र की जनता को शुद्ध वातावरण मिल सकेगा। उन्होंने इस अभियान में एक कदम आगे बढ़ते हुए संकल्प लेने कहा कि हम आज से ही इसको सिरे से नकार देवें।

निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने स्वच्छ व सुंदर भिलाई बनाने के लिए जनता से अपील की कि जन सरोकार के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा करें। साथ ही उन्होंने इसके उपयोग के दुष्प्रभाव को रेखांकित करते हुए कहा कि यह मानव के साथ पशु-पक्षियों के लिए भी बेहद घातक है।

प्लास्टिक में रखकर फेंके खाद्य सामाग्रियों के सेवन से मवेशी भी मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। वहीं कचरे के ढेर से ये सड़कों व नालियों को भी अवरूद्ध कर देते हैं। इससे नालियां भी जाम हो जाती हैं। परिणामस्वरूप नालियां बजबजाने लगती हैं और लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि इसके बहिष्कार से ही शहर सुंदर बन सकता है व वातावरण भी शुद्ध हो सकता है। आयुक्त सर्वे ने लोगों को संकल्प लेने कहा कि आज से ही हम सभी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर देवें।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950